

Weekly One Liners 29th June to 5th July, 2026

सरकार ने EPF स्कीम 2026 को रिवाइज्ड पार्शियल विड्रॉल रूल्स और नई मेंबर सर्विसेज के साथ नोटिफाई किया

केंद्र सरकार ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम, 2026 को नोटिफाई किया है। इसने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) मेंबर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल के नियमों में ज़रूरी बदलाव किए हैं। नई स्कीम 29 जून, 2026 से लागू होगी। इस बदली हुई स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स को कोई भी पार्शियल विड्रॉल करने से पहले अपने EPF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होगा और यह प्रोविडेंट फंड सेविंग्स को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल मकसदों की लिस्ट को भी बढ़ाता है। इन सुधारों के साथ, EPFO मेंबर्स की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए UPI-बेस्ड विड्रॉल और WhatsApp-इनेबल्ड मेंबर सर्विस भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

EPF स्कीम 2026 क्या है?

EPF स्कीम 2026 लेटेस्ट फ्रेमवर्क है जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के मेंबर्स के लिए प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल को कंट्रोल करता है।

नई रिवाइज्ड स्कीम रिटायरमेंट सेविंग्स को बचाने के लिए नए सेफ़गाइर्स लाती है, जिससे उन मेंबर्स को ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिन्हें सच में फ़ाइनेंशियल ज़रूरतें हैं।

यह तेज़ और ज़्यादा आसान मेंबर सर्विस को जोड़कर सरकार के बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा को भी सपोर्ट करता है।

नए 25% मिनिमम बैलेंस नियम के बारे में

इनमें से एक बड़ा बदलाव मिनिमम बैलेंस की ज़रूरी शर्त लागू करना है।

नए नियमों के तहत, EPFO मेंबर्स को कोई भी पार्शियल विड्रॉल करने से पहले अपने EPF अकाउंट में कम से कम 25% बैलेंस रखना होगा।

यह मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया दोनों पर लागू होता है,

- कर्मचारी योगदान
- नियोक्ता योगदान

₹ 1 लाख का एलिजिबल बैलेंस है, तो मेंबर को अकाउंट में ₹ 25,000 रखने होंगे और इससे निकालने के लिए ₹ 75,000 तक अवेलेबल होंगे और यह भी लागू शर्तों के अधीन है।

स्कीम के अनुसार एलिजिबल मेंबर बैलेंस वह रकम है जो ज़रूरी 25% बैलेंस पहले से अलग रखने के बाद मिलती है।

आंशिक निकासी के विस्तृत कारण

नई रिवाइज्ड EPF स्कीम 2026 उन हालात की लिस्ट को और बड़ा करती है जिनमें मेंबर अपनी सेविंग्स निकाल सकते हैं।

1. आवास संबंधी उद्देश्य

योग्य सदस्य अब निम्न के लिए धन निकाल सकते हैं,

घर या फ्लैट खरीदना, घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदना, रहने की प्रॉपर्टी बनाना, घर और घर की मरम्मत और परिवार की ज़रूरतों के लिए लोन का पैसा चुकाना।

2. व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतें

इन हालात में, मेंबर्स एलिजिबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, हायर एजुकेशन और शादी से जुड़े खर्च। ये प्रोविज़न ज़िंदगी की बड़ी मुश्किल घटनाओं के दौरान ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।

निकासी के लिए आसान पात्रता

नई रिवाइज्ड स्कीम में विड्रॉल की शर्तों को भी आसान कर दिया गया है।

मुख्य बदलावों में शामिल हैं,

- 12 महीने की सर्विस के बाद पार्शियल विड्रॉल की इजाज़त है।
- खास हालात में पैसे निकालने के लिए अब और कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं है।
- इसके अलावा, आसान प्रोसेस का मकसद क्लेम की प्रोसेसिंग को तेज़ी से करना है।

इन उपायों से प्रोविडेंट फंड सेविंग्स तक पहुंच बेहतर होने के साथ-साथ रिटायरमेंट की पूरी सुरक्षा बनाए रखने की भी उम्मीद है।

EPFO UPI-बेस्ड PF विड्रॉल शुरू करेगा

ऑर्गनाइजेशन में डिजिटल मॉडर्नाइजेशन के हिस्से के तौर पर, EPFO ने एक ऐसी सुविधा की टेस्टिंग भी पूरी कर ली है जिससे मेंबर्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) का इस्तेमाल करके प्रोविडेंट फंड का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।

एक बार यह लॉन्च हो जाने पर, सब्सक्राइबर्स को ये फ़ायदे होंगे,

- तेज़ दावा निपटान
- तत्काल धन हस्तांतरण
- सरलीकृत निकासी प्रक्रिया
- बेहतर डिजिटल पहुँच

इस पहल से एलिजिबल क्लेम के प्रोसेसिंग टाइम में काफी कमी आने की उम्मीद है।

EPFO सदस्यों के लिए WhatsApp सेवाएँ

EPFO WhatsApp के ज़रिए मेंबर सर्विस शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है।

सब्सक्राइबर EPFO के वेरिफाइड WhatsApp नंबर पर एक सिंपल "Hello" मैसेज भेजकर सर्विस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे।

यह प्लेटफॉर्म सदस्यों को यह करने में मदद करेगा,

- पीएफ बैलेंस चेक करें
- पिछले पाँच अकाउंट ट्रांज़ैक्शन देखें
- दावे की स्थिति ट्रैक करें
- क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाओं तक पहुँच

इस कदम का मकसद एक्सेसिबिलिटी, शिकायत दूर करने और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना भी है।

VB-G RAM G एक्ट 2026 की जानकारी: राज्यवार मज़दूरी दरें, 125 दिन का रोज़गार, मुख्य बदलाव और फ़ायदे

1 जुलाई, 2026 को पूरे देश में नया विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) शुरू किया जाएगा, और इस नए कानून ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह ले ली है। इसका मकसद गांव की रोज़ी-रोटी की सुरक्षा को मज़बूत करना और ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 के विज़न के साथ जोड़ना है।

नए एक्ट, राज्यवार वेतन, रोज़गार गारंटी और बड़े बदलावों के बारे में जानने के लिए यहां सब कुछ है।



LIVE CLASSES

Online **LIVE** Classes for **SSC, Banking, Railways** and Other Govt Exams



**Live & Recorded
Classes**



**PDF Notes &
Study Material**



**Mock Tests &
Practice Questions**



**Doubt Solving
Sessions**

- ✓ **Expert Faculty** with Interactive Classes
- ✓ **Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests**
- ✓ **Courses Available in Hindi, English & Regional Languages**

Get Started Now

VB-G RAM G एक्ट क्या है?

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025 भारत सरकार का नया ग्रामीण रोजगार कानून है, जिसे ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाला मजदूरी वाला रोजगार देने के लिए बनाया गया है।

यह एक्ट यह पक्का करता है कि हर योग्य ग्रामीण परिवार, जिसके बड़े सदस्य अपनी मर्जी से बिना हुनर का काम करने के लिए तैयार हों, को एक फाइनेंशियल ईयर में 125 दिनों की गारंटी वाली मजदूरी वाली नौकरी मिले। रोजगार के मौके बनाने के अलावा, यह स्कीम टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति बनाने और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस करती है।

VB-G RAM G एक्ट के तहत कितने वर्कडेज़ की गारंटी है?

नए कानून के तहत किए गए बड़े बदलावों में से एक गारंटीड रोजगार में बढ़ोतरी है।

VB-G RAM G एक्ट के तहत, हर योग्य ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन का काम मिलना तय है, और इसकी तुलना पिछले MGNREGA फ्रेमवर्क के तहत 100 दिनों से की जाती है।

25 दिन के एक्स्ट्रा गारंटी वाले काम से गांव के परिवारों को ज्यादा इनकम सिक्योरिटी मिलेगी और गांवों में रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे।

वीबी-जी रैम जी एक्ट के मुख्य उद्देश्य

इस एक्ट का मकसद गांव में रहने वालों की रोज़ी-रोटी को बेहतर बनाना और अच्छे पब्लिक कामों के ज़रिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है।

इसके प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल हैं,

- ग्रामीण परिवारों को गारंटीड वेतन वाली नौकरी देना।
- रोज़ी-रोटी की सुरक्षा को मजबूत करना।
- क्लाइमेट-रेज़िलिएंट ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना।
- पानी बचाने और पानी की सुरक्षा में सुधार करना।
- खेती और गांव की रोज़ी-रोटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना।
- खराब मौसम और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में मदद करने वाले कामों को सपोर्ट करना।
- विकसित भारत @2047 के विज़न के साथ ग्रामीण विकास को जोड़ना।

नए एक्ट के तहत किए गए बड़े बदलाव

VB-G RAM G एक्ट, MGNREGA की तुलना में कई स्ट्रक्चरल सुधार लाता है।

1. रोजगार बढ़ाकर 125 दिन किया गया

गारंटीड रोजगार का समय हर फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।

2. उच्च मजदूरी दरें

सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी की दरों में बदलाव किया है।

इस नए वेज स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि देश में कहीं भी किसी भी वर्क को हर दिन ₹ 300 से कम नहीं मिलेगा।

नेशनल एवरेज डेली वेज भी पिछले सिस्टम के तहत लगभग ₹ 298.80 से बढ़ाकर अभी लगभग ₹ 327.40 कर दिया गया है।

3. साप्ताहिक वेतन भुगतान

पहले के पेमेंट साइकिल के उलट, नए एक्ट के तहत सैलरी भी हर हफ्ते दी जाएगी और इससे वर्कर्स को जल्दी फाइनेंशियल मदद मिल सकेगी।

4. जलवायु-अनुकूल विकास पर ध्यान

यह एक्ट उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देता है जिनमें शामिल हैं,

- जल संरक्षण
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- आजीविका से संबंधित संपत्तियाँ
- जलवायु अनुकूलन
- चरम मौसम शमन

5. विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ

हर ग्राम पंचायत नए फ्रेमवर्क के तहत डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी ताकि यह पक्का हो सके कि रोजगार प्रोजेक्ट आसानी से लोकल डेवलपमेंट की ज़रूरतों को पूरा करें।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक

यह एक्ट विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक नाम का एक यूनिफाइड प्लानिंग सिस्टम बनाता है, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए PM गति शक्ति इनिशिएटिव के साथ रूरल प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है।

7. खेती के पीक सीजन के दौरान काम रोकने का प्रावधान

खेती के कामों के दौरान मजदूरों की कमी से बचने के लिए, राज्य सरकारें बुवाई और कटाई के मौसम में कुछ समय के लिए काम रोक सकती हैं।

राज्यों को लोकल फसल पैटर्न और खेती-बाड़ी के मौसम के आधार पर, इन समयों के बारे में लगभग 60 दिन पहले बताना होगा।

नए वीबी-जी रैम जी एक्ट के तहत राज्यवार दैनिक मजदूरी दरें

एक्ट के तहत नोटिफाई की गई रिवाइज्ड मिनिमम डेली वेज रेट्स हैं,

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दैनिक मजदूरी
आंध्र प्रदेश	₹ 307
अरुणाचल प्रदेश	₹ 300
असम	₹ 300
बिहार	₹ 300
गोवा	₹ 406
गुजरात	₹ 316
हिमाचल प्रदेश	₹ 328
हरियाणा	₹ 409
छत्तीसगढ़	₹ 300
झारखंड	₹ 300
कर्नाटक	₹ 349
केरल	₹ 401
Ladakh	₹ 300
Maharashtra	₹ 312
Madhya Pradesh	₹ 300
Manipur	₹ 300
Meghalaya	₹ 300
Nagaland	₹ 300
Mizoram	₹ 300
Odisha	₹ 300

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	दैनिक मजदूरी
Punjab	₹336
Rajasthan	₹308
Sikkim	₹450
Tamil Nadu	₹ 336
तेलंगाना	₹ 307
त्रिपुरा	₹ 300
उत्तर प्रदेश	₹ 300
उत्तराखंड	₹ 300
पश्चिम बंगाल	₹ 300
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	₹ 300
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	₹ 300
पुदुचेरी	₹ 300
लक्षद्वीप	₹ 300
जम्मू और कश्मीर	₹ 300

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सिक्किम में लगभग ₹ 450 के साथ सबसे अधिक अधिसूचित दैनिक मजदूरी है, उसके बाद हरियाणा (₹ 409), गोवा (₹ 406) और केरल (₹ 401) का स्थान है।

नया केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न

यह एकट केंद्र और राज्यों के बीच एक बदला हुआ फाइनेंशियल शेयरिंग मैकेनिज्म भी लाता है।

फंडिंग पैटर्न इस प्रकार है,

- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और पात्र केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 (केंद्र : राज्य)।
- 60:40 (केंद्र : राज्य) अन्य सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए।
- बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सेंट्रल फंडिंग। राज्य सरकारों को भी एकट लागू होने के छह महीने के अंदर लागू करने की स्कीम तैयार करनी होगी।

भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 19 बड़ी पहलों की शुरुआत की

भारत और सेशेल्स ने बाइलेटरल पार्टनरशिप को मजबूत किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन दिन के देश दौरे के दौरान कुल 19 पहलों पर साइन किए गए। सहयोग के क्षेत्र हैं समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल पेमेंट, हेल्थकेयर, स्पेस सहयोग, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दोनों देशों के बीच बाइलेटरल बातचीत विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ हुई।

प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा के नतीजे

28 जून 2026 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक हर्मिनी ने मिलकर कुल 19 नतीजे पेश किए, जिनका मकसद कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आपसी रिश्तों को गहरा करना है।

इन पहलों का फोकस डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, एजुकेशन को सपोर्ट करना और आउटर स्पेस और क्लाइमेट रेजिलिएंस में कोऑपरेशन बढ़ाना है।

इस दौरे में हिंद महासागर में "नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर" के तौर पर भारत के विज्ञान पर भी ज़ोर दिया गया, साथ ही देश के MAHASAGAR (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स) इनिशिएटिव के तहत आइलैंड देशों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत किया गया।

19 नतीजों की खास बातें

ये एग्रीमेंट कई तरह के सेक्टर में फैले हुए हैं, जिनमें शामिल हैं,

- समुद्री सुरक्षा सहयोग
- रक्षा सहयोग
- प्रत्यर्पण संधि
- बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग
- UPI-आधारित डिजिटल भुगतान
- स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना
- शिक्षा और कौशल विकास
- कृषि और खाद्य सुरक्षा
- बुनियादी ढांचा सहायता
- ऋण व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय सहयोग

भारत ने समुद्री और रक्षा सहयोग को मजबूत किया

समुद्री सुरक्षा भारत-सेशेल्स संबंधों की नींव बनी हुई है।

इस यात्रा के हिस्से के तौर पर, भारत ने कई रक्षा सहायता उपायों की घोषणा की है, जैसे,

- स्वदेश निर्मित तीव्र गश्ती पोत का उपहार
- 10 यूटिलिटी वाहनों का दान
- लगभग पांच लेजर रेडियल क्लास सेलिंग बोट की सप्लाई
- सेशेल्स कोस्ट गार्ड के लिए PS ज़ोरोस्टर का रिफिट पूरा हुआ
- डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान को मॉडर्न ग्लास कॉकपिट के साथ अपग्रेड किया गया

महासागर विज्ञान को मजबूत करना

जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के MAHASAGAR विज्ञान को दोहराया है, जो सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरक्की है।

इस पहल का मकसद है,

- सुरक्षित और संरक्षित समुद्री मार्ग
- समुद्री सहयोग
- सतत आर्थिक विकास
- आपदा तैयारी
- नीली अर्थव्यवस्था साझेदारियां
- क्षेत्रीय शांति और स्थिरता

उन्होंने हिंद महासागर को "मौके का महासागर" भी बताया, जो भारत की लंबे समय की क्षेत्रीय रणनीति को दिखाता है।

डिजिटल, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग

दोनों देश नई टेक्नोलॉजी में अपने सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं।

प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं,

- यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान
- बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग
- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचा समर्थन

इसमें शामिल है,

- नए सेशेल्स नेशनल हॉस्पिटल की शुरुआती तैयारियों के लिए एग्रीमेंट
- प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सेंटर के लिए वर्चुअल ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता

भारत ने मानवीय सहायता भी दी,

- 500 मीट्रिक टन चावल
- 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट

विशेष आर्थिक पैकेज और खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने यह भी कन्फर्म किया है कि दोनों देश पहले से घोषित US\$175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर बातचीत जारी रखेंगे। इस पैकेज की घोषणा सबसे पहले फरवरी 2026 में उनके भारत दौरे के दौरान की गई थी और इसमें ये भी शामिल थे,

- 1,000 मीट्रिक टन अनाज और दालें
- सेशेल्स की खाद्य सुरक्षा पहलों के लिए समर्थन

यह लगातार जुड़ाव छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाता है।

सेशेल्स और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन

सेशेल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव (CSC) के छह सदस्यों में से एक है, यह एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें शामिल हैं,

- भारत
- बांग्लादेश
- मालदीव
- मॉरीशस
- सेशेल्स
- श्रीलंका

भारत इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बेहतर बनाने के लिए कॉन्क्लेव को एक्टिवली मजबूत कर रहा है।

'ब्लू होराइजन के संरक्षक' सम्मान

माननीय राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइजन" की मानद उपाधि भी दी है।

यह पुरस्कार उनके,

- पर्यावरण संरक्षण में नेतृत्व
- जलवायु कार्रवाई के लिए समर्थन
- छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के प्रति प्रतिबद्धता
- सतत महासागर शासन को बढ़ावा देना

यह सम्मान PM मोदी को किसी दूसरे देश से मिला 34वां इंटरनेशनल अवॉर्ड भी बन गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के 'गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइजन' राष्ट्रपति पद का सम्मान मिला

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइजन' प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के माननीय राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने 28 जून, 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री को यह अवॉर्ड दिया। यह पहचान क्लाइमेट एक्शन, ब्लू इकॉनमी प्रमोशन, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में PM मोदी की बढ़ती भूमिका को दिखाती है।

'गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइजन' प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन के बारे में 'गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइजन' प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन एक प्रतिष्ठित सिविलियन सम्मान है जिसे सेशेल्स गणराज्य ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवॉर्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, जो दुनिया में बेहतरीन ग्लोबल लीडरशिप को पहचान देता है।

- जलवायु कार्रवाई
- पर्यावरण संरक्षण
- समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन
- नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
- छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए समर्थन
- सतत विकास पहल

यह सम्मान उन इंटरनेशनल लीडर्स के लिए सेशेल्स की तारीफ़ को दिखाता है जिन्होंने मरीन इकोसिस्टम को बचाने और ग्लोबल एनवायरनमेंटल चुनौतियों से निपटने में अहम योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित क्यों किया गया?

सेशेल्स सरकार के अनुसार, यह अवॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डेवलपिंग देशों के हितों के प्रति लंबे समय से चले आ रहे कमिटमेंट को देखते हुए दिया गया।

यह सम्मान, को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देता है,

- वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई
 - सतत महासागर शासन
 - नीली अर्थव्यवस्था पहल
 - हरित विकास
 - पर्यावरण संरक्षण
 - छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- यह पहचान आइलैंड देशों के बीच एनवायरनमेंटल रेजिलिएंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है।

सेशेल्स द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण पहल

यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई या प्रमोट की गई कई बड़ी पहलों पर रोशनी डालता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
- एक पेड़ माँ के नाम
- अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन

ये पहल मिलकर दिखाती हैं कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने पर कितना ज़ोर दे रहा है।

भारत-सेशेल्स संबंधों को मजबूत करना

यह अवॉर्ड ऐसे खास मौके पर मिला है, जब भारत और सेशेल्स डिप्लोमैटिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

सम्मान स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह पहचान उन सभी देशों को समर्पित की जो पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि यह अंतर भारत और सेशेल्स के बीच पुरानी दोस्ती को और मजबूत करेगा, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समुद्री सुरक्षा में उनके सहयोग को और मजबूत करेगा।

RBI की नई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 1 जुलाई से लागू होगी: मुख्य बातें, शिकायत प्रक्रिया और फायदे

1 जुलाई, 2026 से, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने अपनी नई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लागू की है। यह स्कीम फाइनेंशियल कंपनियों के खिलाफ कस्टमर की शिकायतों को हल करने के लिए फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यह 2021 की स्कीम की जगह ले रही है और इस नए सिस्टम का मकसद एक फ्री, तेज़, ट्रांसपेरेंट शिकायत सुलझाने का सिस्टम देना है।

RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है?

इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर्स के लिए RBI का यूनिफाइड शिकायत निवारण सिस्टम है।

इस स्कीम से कस्टमर्स को कई अथॉरिटीज़ के पास जाए बिना, इन-सर्विस से जुड़ी शिकायतों का हल ढूंढने में मदद मिलती है।

यह "एक देश, एक लोकपाल" सिद्धांत को मानता है और यह पक्का करता है कि कस्टमर की लोकेशन या रेगुलेटेड एंटीटी की लोकेशन की परवाह किए बिना प्रोसेस किया जाए।

यह बदला हुआ फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2021 की जगह लेगा, जबकि पहले वाली स्कीम के तहत फाइल की गई शिकायतों को पिछले नियमों के हिसाब से ही हैंडल किया जाता रहेगा।

कवर किए जाने वाले संस्थान

नई बदली हुई स्कीम RBI-रेगुलेटेड एंटीटीज़ की कई कैटेगरी तक अपना कवरेज बढ़ाती है, जिसमें शामिल हैं,

- शेड्यूल्ड और कमर्शियल बैंक।
- योग्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)।
- प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाले।
- क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CICs)।

इस बड़े कवरेज से ज़्यादा फाइनेंशियल कंज्यूमर्स को सिंगल और स्टैंडर्ड शिकायत निवारण सिस्टम का इस्तेमाल करने में भी मदद मिलती है।

शिकायत प्रोसेस कैसे काम करता है?

नए फ्रेमवर्क में शिकायत दर्ज करने के लिए साफ़ स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताया गया है।

स्टेप 1: रेगुलेटेड एंटीटी से संपर्क करें

कस्टमर्स को सबसे पहले अपनी शिकायत संबंधित बैंक, NBFC, PPI जारी करने वाली कंपनी या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी होगी।

स्टेप 2: जवाब का इंतज़ार करें

अगर एंटीटी,

- 30 दिनों के अंदर (या RBI, NPCI, या लागू कार्ड नेटवर्क नियमों द्वारा तय ज़्यादा समय के अंदर) जवाब नहीं देता है, या
- वह जवाब देता है जो ग्राहक को ठीक नहीं लगता, तो शिकायत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

स्टेप 3: RBI लोकपाल से संपर्क करें

कस्टमर फ़ाइनल जवाब मिलने के 90 दिनों के अंदर या जवाब का समय खत्म होने के बाद RBI ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यह स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रेगुलेटेड एंटीटीज़ को शिकायतों को पहले लेवल पर हल करने के लिए बढ़ावा देता है, साथ ही अनसुलझे मामलों के लिए इंडिपेंडेंट रास्ता पक्का करता है।

नई योजना की मुख्य विशेषताएं

रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कई ज़रूरी सुधार किए गए हैं, जैसे,

- एक राष्ट्र, एक लोकपाल फ्रेमवर्क।
- पूरे भारत में एक जैसी शिकायत हैंडलिंग।
- बिना किसी खर्च के शिकायत का समाधान।
- बिना विरोध के विवाद सुलझाने की प्रक्रिया।
- शिकायतों की जांच में डिप्टी ओम्बड्समैन की भूमिका बढ़ाई गई।
- शिकायतों के लिए साफ़ तौर पर तय मेटेनस क्राइटेरिया।
- ऑनलाइन और आसान शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस।

RBI ने कस्टमर्स को नए फ्रेमवर्क को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए एक डिटेल्ड अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) डॉक्यूमेंट भी जारी किया है।

नए फ्रेमवर्क के तहत सुआवज़ा

जहां लोकपाल को सेवा में कमी मिलती है, तो वह,

- रेगुलेटेड एंटीटी को करेक्टिव एक्शन लेने का निर्देश देता है।
- और फाइनेंशियल नुकसान के लिए सुआवज़ा देता है।

सुआवज़े की सीमाएँ हैं,

- इसके बाद हुए फ़ाइनेंशियल नुकसान के लिए ₹ 30 लाख तक का सुआवज़ा।
- समय की हानि, खर्च, परेशानी और मानसिक परेशानी के लिए ₹ 3 लाख तक का सुआवज़ा।

राष्ट्रीय समाचार

- कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटरी पोर्टल पर फ़्रेश एप्लीकेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है, ताकि योग्य वकील और कानूनी पेशेवर नोटरी एक्ट, 1952 और नोटरी रूल्स, 1956 के तहत नोटरी पब्लिक के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ मिलकर बनाया गया यह पोर्टल पेपरलेस एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड स्कूटनी, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग देता है, जिससे देरी और कागजी कार्रवाई कम होती है। एप्लीकेशन खाली जगहों और इलाके की ज़रूरतों के आधार पर मंगाए जाएंगे। यह पहल देश भर में एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी में सुधार और कानूनी एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाकर डिजिटल इंडिया को मजबूत करती है।
- नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत सर्विसेज़ तक पहुंच को आसान बनाने के लिए WhatsApp पर आधारित चैटबॉट आयुष्मान सारथी लॉन्च किया है। बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी वेरिफाई कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई और डाउनलोड कर सकते हैं, e-KYC पूरा कर सकते हैं, आधार लिंक कर सकते हैं, पैनल वाले हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं और सिक्योर API इंटीग्रेशन के ज़रिए फीडबैक दे सकते हैं। चैटबॉट 24x7 काम करता है, जिससे सरकारी ऑफिसों पर डिपेंडेंस कम होती है और सर्विस डिलीवरी तेज़ और ट्रांसपेरेंट होती है। यह पहल डिजिटल इंडिया, पेपरलेस गवर्नेंस, बेहतर हेल्थकेयर एक्सेसिबिलिटी, कुशल एडमिनिस्ट्रेशन और देश भर के लाखों बेनिफिशियरी के लिए नागरिक-केंद्रित डिजिटल हेल्थकेयर सर्विसेज़ को बढ़ावा देती है।

- भारत सरकार ने जन्म से 36 महीने तक के बच्चों के लिए हेल्थकेयर को मजबूत करने के लिए समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (SSBSK) शुरू किया है। इसके लिए नवजात और बचपन की हेल्थ सर्विस को एक साथ लाया गया है। यह प्रोग्राम कम वजन वाले, कुपोषित, समय से पहले जन्मे और विकास में कमजोर बच्चों को प्राथमिकता देता है। इसके लिए घर पर ज्यादा विजिट, शुरुआती स्क्रीनिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग और फ्रंटलाइन वर्कर समय पर रेफरल करते हैं। यह न्यूट्रिशन, ब्रेस्टफीडिंग, बच्चों के विकास और स्क्रीन पर कम समय बिताने के बारे में जागरूकता भी बढ़ाता है। डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से लगातार मॉनिटरिंग होती है, जिसका मकसद बच्चों के बचने की क्षमता, स्वस्थ विकास और कम्युनिटी-बेस्ड हेल्थकेयर डिलीवरी को बेहतर बनाना है।
- भारत सरकार ने समुद्री और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मिनिस्ट्री के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) बनाया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) की तरह, BoPS पोर्ट और शिप सिक्योरिटी के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) के तहत काम करेगा। CISF को सिक्योरिटी असेसमेंट, प्लानिंग और ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन के तौर पर बनाया गया है। यह पहल भारत के ज़रूरी समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर रेजिलिएंस, रेगुलेटरी कम्प्लायंस और सुरक्षा को बढ़ाती है।
- भारत ने ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में पाँच मेडल जीते, जिसमें 23-29 जून 2026 तक हुए कॉम्पिटिशन में तीन गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीते। वर्ल्डस्किल्स शंघाई की तैयारी के लिए 16 देशों के लगभग 600 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। भारतीय पार्टिसिपेंट्स ने क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिटिव मैनुफैक्चरिंग, हेल्थ और सोशल केयर, और डिजिटल गेम आर्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि स्किल इंडिया मिशन की सफलता को दिखाती है, भारत के ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव वोकेशनल टैलेंट को दिखाती है, टेक्निकल करियर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है, और इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट में देश की रेप्रेजेंटेशन को मजबूत करती है।
- भारत टैक्सी को गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 जून 2026 को "सहकार से समृद्धि" के विज़न के तहत एक कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर लॉन्च किया था। प्राइवेट एग्रीगेटर्स के उलट, ड्राइवर (सारथी) शेयरहोल्डर बन जाते हैं, जिससे ओनरशिप, ज्यादा कमाई, इंश्योरेंस, लोन, वेलफेयर और ट्रांसपेरेंसी पक्की होती है। यह प्लेटफॉर्म टू-व्हीलर, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों को सपोर्ट करता है। 7 लाख से ज्यादा सारथी और 37 लाख कस्टमर पहले ही इससे जुड़े हुए हैं। शुरुआत में गुजरात में लॉन्च किया गया, इसका मकसद 31 जुलाई तक सात शहरों और दो साल के अंदर 500+ शहरों में बड़े कोऑपरेटिव और ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट से इसे बढ़ाना है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, "गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन" प्रेसीडेंशियल डिस्टिंक्शन के पहले प्राप्तकर्ता बने, जिसे 28 जून 2026 को राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जलवायु कार्रवाई, नीली अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, महासागर शासन और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) के लिए समर्थन में नेतृत्व को मान्यता देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), मिशन LiFE, एक पेड़ माँ के नाम और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस सहित भारत की पहलों को स्वीकार करता है। भारत-सेशेल्स राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के दौरान प्रस्तुत किया गया, यह समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय जलवायु लचीलेपन में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करता है।
- अपने सेशेल्स दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स नेशनल बोटेनिकल गार्डन गए, जहाँ वे दुनिया के सबसे बड़े ज़मीन पर रहने वाले जानवर जोनाथन से मिले। जोनाथन, एक सेशेल्स का बड़ा कछुआ, लगभग 1832 में पैदा हुआ था और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसकी उम्र लगभग 194 साल है। वह सेंट हेलेना, एक ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी में रहता है। मोदी ने एक पेड़ भी लगाया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, बायोडायवर्सिटी सुरक्षा, क्लाइमेट रेजिलिएंस, मिशन LiFE, और एक पेड़ माँ के नाम पर ज़ोर दिया गया। यह दौरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल पर्यावरण सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट का प्रतीक था।
- गुजरात ने 28 जून 2026 को मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर को मजबूत करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर PM फैमिली केयर ट्रैकर (PM-FCT) और हेल्थ पासपोर्ट लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेग्रेसी से लेकर 16-18 साल तक के बेनिफिशियरीज़ को ट्रैक करता है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर डेटाबेस को इंटीग्रेट किया गया है। यह छूटे हुए वैक्सिनेशन और स्कूल छोड़ने वालों के लिए ऑटोमैटिक अलर्ट जेनरेट करता है, जिससे समय पर सरकारी दखल दिया जा सके। जुड़े हुए डिपार्टमेंट में हेल्थ, महिला और बाल विकास और एजुकेशन शामिल हैं। Viksit Gujarat @2047 और Viksit India @2047 को सपोर्ट करते हुए, यह इंटीग्रेटेड डिजिटल गवर्नेंस और वेलफेयर डिलीवरी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 29 जून 2026 को एनीमिया मुक्त भारत अभियान की रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2026 जारी कीं, जिसमें सात बेनिफिशियरी ग्रुप्स, सात इंटरवेंशन्स और सात इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को कवर करते हुए 7x7x7 स्ट्रैटेजी शुरू की गई। यह प्रोग्राम एक लाइफ-साइकल अप्रोच अपनाता है, जिसमें कम वजन वाले बच्चों (0-6 महीने) को एक नए टारगेट ग्रुप के तौर पर शामिल किया गया है, और आयरन से भरपूर डाइट को बढ़ावा देने के लिए "ईटिंग राइट" को जोड़ा गया है। यह फ्रेमवर्क T3 (टेस्ट, ट्रीट, टॉक) से T4 (टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक) में अपग्रेड होता है और JANANI, RBSK, और U-WIN प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करता है, जिससे देश भर में एनीमिया की रोकथाम, मॉनिटरिंग, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड न्यूट्रिशन मजबूत होता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब-सेंटर और छोटे आउटपैशेंट क्लिनिक के लिए C-DAC द्वारा डेवलप किया गया क्लाउड-बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) e-Sushrut@Clinic लॉन्च किया है। 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया, यह मरीज़ रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, MIS रिपोर्टिंग को डिजिटाइज़ करता है, और क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट के साथ स्पीच-टू-टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन देता है। क्लाउड होस्टिंग और SMS सर्विस के ज़रिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) द्वारा सपोर्टेड, यह हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री (HFR) के साथ इंटीग्रेट होता है। 800 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी पहले ही ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

- टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भारत के टूरिज्म डेस्टिनेशन की डिजिटल विजिविलिटी बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में, यह एग्रीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा-ड्रिवन इनसाइट्स का इस्तेमाल करके कल्चरल, हिस्टोरिकल, स्परिचुअल और नेचुरल अट्रैक्शन की डिस्कवरेबिलिटी को बेहतर बनाता है। यह पर्सनलाइज्ड विजिटर एंगेजमेंट, ट्रैवल ट्रेड एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और ऑफिशियल ट्रेनिंग को सपोर्ट करता है। यह नॉन-कमर्शियल, नॉन-बाइंडिंग MoU डिजिटल इंडिया, सस्टेनेबल टूरिज्म और भारत की ग्लोबल टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देते हुए इनक्रेडिबल इंडिया कैम्पेन को मजबूत करता है।
- विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025, 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ, जिसने पहले के ग्रामीण रोजगार फ्रेमवर्क की जगह ली। यह एक्ट हर योग्य ग्रामीण परिवार के लिए गारंटी वाले रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है और टिकाऊ संपत्ति बनाने, पानी बचाने, पारदर्शी शासन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। सरकार ने पूरे देश में इसे लागू करने के लिए ₹ 95,692.31 करोड़ दिए। यह सेल्फ-हेल्प ग्रुप (SHG) की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, टेक्नोलॉजी से चलने वाले काम और बेहतर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देता है। मौजूदा लाभार्थियों को बदलाव के दौरान बिना किसी रुकावट के फायदे मिलते रहेंगे।
- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने 2018 में टाइगर रिजर्व को ट्रांसलोकेशन की नाकाम कोशिश के बाद, ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 2024 के असेसमेंट में यह कन्फर्म हुआ कि यहाँ टाइगर नहीं हैं और रीइंट्रोडक्शन से पहले हैबिटेट में सुधार की सलाह दी गई है। 1,136 sq km में फैला यह रिजर्व, जिसमें 523 sq km का कोर एरिया शामिल है, टाइगर के लिए सही हैबिटेट देता है। सुझाए गए उपायों में गाँवों को दूसरी जगह बसाना, शिकार के ठिकानों को बढ़ाना, शिकार रोकने की कोशिशें, स्टाफ ट्रेनिंग और टकराव कम करना शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडायवर्सिटी और टाइगर की एक सस्टेनेबल आबादी को फिर से बनाना है।
- व्हाइट-रम्पड वल्वर (जिप्स बेंगालेंसिस) IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बना हुआ है। इसकी आबादी में भारी गिरावट मुख्य रूप से डाइक्लोफेनाक, दूसरे नुकसानदायक NSAIDs, खराब लाशों, बिजली के झटके, रहने की जगह के नुकसान और शहरीकरण की वजह से हुई है। गिद्ध जानवरों की लाशों को हटाकर बीमारी फैलने से रोकते हैं। भारत कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, 700 से ज्यादा गिद्धों को छोड़ने की योजना बना रहा है, जबकि कीटोप्रोफेन और निमेसुलाइड जैसी नुकसानदायक जानवरों की दवाओं पर बैन लगा रहा है। नेपाल और कंबोडिया में बचाव की कोशिशें, GPS ट्रैकिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग के साथ, लंबे समय तक प्रजातियों की रिकवरी में मदद करती हैं।
- भारत सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 30 जून 2026 को FCRA 2.0 पोर्टल और ई-ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया (e-OCI) कार्ड लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया FCRA 2.0 पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, कम्प्लायंस मॉनिटरिंग, आधार ऑथेंटिकेशन, ई-सिग्रेचर, OCR वेरिफिकेशन और PAN, NGO दर्पण और UDIN के साथ इंटीग्रेशन को सुमकिन बनाता है। ई-OCI कार्ड मौजूदा OCI कार्ड की वैलिडिटी बनाए रखते हुए ऑनलाइन अपडेट और डिजिटल रिकॉर्ड के ज़रिए ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया सर्विसेज़ को डिजिटलाइज़ करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस में सुधार होता है।
- NEP 2020 के तहत, भारत एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट्स (ABC) और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (APAAR) के ज़रिए शिक्षा को बदल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा मैनेज किया जाने वाला ABC, स्टूडेंट्स को अलग-अलग संस्थानों में एकेडमिक क्रेडिट स्टोर करने, ट्रांसफर करने, जमा करने और रिडीम करने में मदद करता है। APAAR, एक 12-डिजिट की लाइफलाइन स्टूडेंट ID है, जो स्कूल और हायर एजुकेशन रिकॉर्ड को DigiLocker और ABC के साथ इंटीग्रेट करता है। साथ मिलकर, वे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, एकेडमिक मोबिलिटी, SWAYAM के ज़रिए ऑनलाइन लर्निंग और प्लेक्सिबल डिग्री कम्प्लीशन को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और स्टूडेंट-सेंट्रिक एजुकेशन इकोसिस्टम बनता है।
- केंद्रीय कैबिनेट ने ₹ 14,114.81 करोड़ के दो हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली में 8.1 km लंबी छह लेन की टनल और उत्तर प्रदेश में 117.7 km लंबा कानपुर-कबराई ग्रीनफील्ड हाईवे शामिल है। हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत बनी दिल्ली टनल, टनल बोरिंग मशीन (TBM) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सदरन रिज फॉरेस्ट के नीचे 3.14 km लंबी ट्विन-ट्यूब टनल के ज़रिए द्वारका एक्सप्रेसवे को नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। NHAI द्वारा BOT मॉडल के तहत बनाया गया यह हाईवे यात्रा के समय को 3.5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर देगा, कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और रोजगार पैदा करेगा।
- भारत की सबसे बड़ी तितली और कर्नाटक की स्टेट बटरफ्लाई, सदरन बर्डविंग (ट्रोइड्स मिनोस) को पहली बार तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में देखा गया है। पैपिलियोनिडे परिवार से जुड़ी और दक्षिण भारत की एंडेमिक, यह मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट में पाई जाती है और IUCN रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न के तौर पर लिस्ट किया गया है। ईस्टर्न घाट की नल्लामाला हिल्स में इसे देखने से तेलंगाना के बायोडायवर्सिटी रिकॉर्ड बेहतर हुए हैं और अमराबाद टाइगर रिजर्व की इकोलॉजिकल अहमियत पर रोशनी पड़ी है।
- भारत सरकार ने मेटा को WhatsApp के यूज़रनेम फ़ीचर के रोलआउट को कुछ समय के लिए रोकने और तीन दिन के अंदर पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है। यह फ़ीचर यूज़र्स को मोबाइल नंबर के बजाय यूनिक यूज़रनेम से बात करने देगा, जिससे प्राइवसी बढ़ेगी। हालांकि, सरकार ने प्राइवसी सेफ़गार्ड, आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेसबिलिटी, इम्पर्सनेशन रिस्क, फ़िशिंग, धोखाधड़ी की रोकथाम और भारतीय कानूनों के पालन को लेकर चिंता जताई है। जब तक बातचीत पूरी नहीं हो जाती, मेटा को भारत में यह फ़ीचर लॉन्च न करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मजबूत डिजिटल गवर्नेंस और यूज़र प्रोटेक्शन पक्का हो सके।

- यह मज़बूत घरेलू प्रोडक्शन और सरकार की इम्पोर्ट सब्सिडिज़ेशन स्ट्रेटेजी को दिखाता है। पावर सेक्टर का इम्पोर्ट 24.89% गिरा, जबकि इम्पोर्टेड कोल-बेस्ड (ICB) प्लांट्स में सबसे ज़्यादा 27.45% की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू कोल-बेस्ड (DCB) प्लांट्स के लिए इम्पोर्ट भी 11.26% कम हुआ। कुल खपत में कोयले के इम्पोर्ट का हिस्सा 21.69% से घटकर 19.68% हो गया, जबकि स्टील की मांग के कारण कोकिंग कोल का इम्पोर्ट 1.34% बढ़ा। बेहतर लॉजिस्टिक्स, फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी और घरेलू सप्लाय ने एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत किया।
- MANAS (मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र), भारत की नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन, नागरिकों को बिना नाम बताए ड्रग की तस्करी, बेचने और गैर-कानूनी खेती की रिपोर्ट करने में मदद करके नशा मुक्त भारत के विज़न को मज़बूत करती है। इसे गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के साथ मिलकर शुरू किया था। यह 1933 हेल्पलाइन, UMANG ऐप, वेब पोर्टल और ईमेल के ज़रिए काम करता है। यह प्लेटफॉर्म कॉल करने वालों को 14446 नशा मुक्ति हेल्पलाइन से भी जोड़ता है, जिसमें काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन सपोर्ट, कई भाषाओं वाली सर्विस, चैटबॉट इंटीग्रेशन, स्मार्ट IVRS और देश भर की एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल की सुविधा मिलती है।
- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश से पूरे देश में विकसित भारत - G-RAM G एक्ट लॉन्च किया, जिसमें हर योग्य ग्रामीण परिवार के लिए हर साल 125 दिन की मज़दूरी वाली नौकरी की कानूनी गारंटी दी गई है। पिछली 100-दिन की रोज़गार गारंटी की जगह, यह स्कीम काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता देती है। केंद्र पहले साल में ₹ 95,000 करोड़ से ज़्यादा का योगदान देगा, जिसमें ₹ 7.5 लाख करोड़ का लंबे समय का निवेश होगा। ग्राम सभाएँ डेवलपमेंट प्लानिंग को लीड करेंगी, जबकि आंध्र प्रदेश को ₹ 7,707 करोड़, 74,212 PMAY-G घर और बड़े PMGSY-IV इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले।
- नीति आयोग ने पीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर “आयुर्वेद को वैश्विक बनाने के लिए रणनीतिक रोडमैप” जारी किया, जिसमें 2047 तक के चरणबद्ध विज्ञान की रूपरेखा दी गई है। रोडमैप का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय नैदानिक परीक्षणों, वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैज्ञानिक सत्यापन और पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) के आधुनिकीकरण के ज़रिए आयुर्वेद को साक्ष्य-आधारित वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में स्थापित करना है। यह एक पेटेंट-वाँच प्रणाली, जिनेवा, न्यूयॉर्क और टोक्यो में वैश्विक आयुर्वेद केंद्र और चिकित्सा मूल्य यात्रा क्षेत्रों का प्रस्ताव करता है। 2014 और 2023 के बीच आयुष निर्यात दोगुना होने के साथ, रोडमैप आयुष मंत्री के नेतृत्व में संस्थागत शासन के तहत वैश्विक बाजार विस्तार का समर्थन करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने व्हाट्सएप को पहले दिए गए नोटिस के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को उनके यूजरनेम-आधारित कम्युनिकेशन फीचर्स के बारे में नोटिस जारी किए। सरकार ने चिंता जताई कि गुमनाम यूजरनेम धोखाधड़ी, फिशिंग, प्रतिरूपण और डिजिटल अरेस्ट स्कैम को आसान बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म को तीन दिनों के अंदर सुरक्षा उपायों, पहचान वेरिफिकेशन

- सिस्टम और गलत इस्तेमाल को रोकने के तरीके समझाने के लिए कहा गया। इस बीच, ज़ोहो समर्थित अराटाई ने यूजरनेम-आधारित अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया। यह कदम डिजिटल गवर्नेंस, यूजर अकाउंटेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय नियमों के पालन को मज़बूत करने पर भारत के फोकस को दिखाता है।
- UIDAI ने आधार ऐप के ज़रिए एक फ्री ईमेल अपडेट सर्विस शुरू की है, जिससे यूजर्स आधार सेवा केंद्र जाए बिना डिजिटली अपनी ईमेल ID जोड़ या अपडेट कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से छह महीने के लिए फ्री में उपलब्ध यह सर्विस, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रियल-टाइम नोटिफिकेशन भेजकर सुविधा, सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। दो दिनों के अंदर, 2.5 लाख से ज़्यादा यूजर्स ने अपनी ईमेल ID अपडेट की। यह ऐप मोबाइल नंबर, पता और दूसरे एलिजिबल अपडेट को भी सपोर्ट करता है, जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को अपनाने और पूरे भारत में नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस में सुधार को दिखाता है।
- ACME ग्रुप ने मित्सुबिशी गैस केमिकल (MGC) के साथ लगभग US\$1 बिलियन का एग्रीमेंट किया है। यह एग्रीमेंट ओडिशा में अपनी आने वाली पारादीप फैसिलिटी से हर साल 100,000 टन ग्रीन मेथनॉल सप्लाय करने के लिए किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके बनाया गया यह फ्यूल, EU RFNBO और भविष्य के IMO स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए जापान के शिपिंग सेक्टर को सपोर्ट करेगा। यह डील इंडिया-जापान क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन को मज़बूत करती है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करती है, एक लॉन्ग-टर्म एक्सपोर्ट मार्केट सुरक्षित करती है, सस्टेनेबल फ्यूल को बढ़ावा देती है, और ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल लो-कार्बन सप्लाय चेन में भारत की लीडरशिप को बढ़ाती है।
- सरकार ने e-OCI कार्ड लॉन्च किया है, जिससे एलिजिबल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डहोल्डर्स स्मार्टफोन पर अपने OCI कार्ड का सिक्योर डिजिटल वर्जन रख सकते हैं। OCI सर्विसेज पोर्टल के ज़रिए एक्सेसिबल, यह इमिग्रेशन अथॉरिटी और एयरलाइंस द्वारा डिजिटल वेरिफिकेशन की इजाज़त देकर ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाता है। सरकार ने साफ़ किया कि फिजिकल OCI बुकलेट पूरी तरह से वैलिड है, जबकि डिजिटल वर्जन ऑप्शनल है। यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करती है, ट्रैवल को आसान बनाती है, डॉक्यूमेंट खोने के रिस्क को कम करती है, और दुनिया भर में लाखों OCI कार्डहोल्डर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाती है।
- केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश के दादरी में AP मोलर-मार्सक के लिए बने भारत के पहले एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया। साथ ही, माएस्क ने DCM श्रीराम ग्रुप के साथ 1,000 अतिरिक्त कंटेनरों का ऑर्डर दिया, जो एक लंबे समय की साझेदारी को दर्शाता है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 को सपोर्ट करती है, साथ ही ₹ 10,000 करोड़ की कंटेनर मैनुफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (CMPS) को भी सपोर्ट करती है। इसका मकसद घरेलू मैनुफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोज़गार, सप्लाय-चेन में लचीलापन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और भारत को हाई-क्वालिटी शिपिंग कंटेनर के लिए ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है।



LIVE CLASSES

Online **LIVE** Classes for **SSC, Banking, Railways** and Other Govt Exams



**Live & Recorded
Classes**



**PDF Notes &
Study Material**



**Mock Tests &
Practice Questions**



**Doubt Solving
Sessions**

- ✓ **Expert Faculty** with Interactive Classes
- ✓ **Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests**
- ✓ **Courses Available in Hindi, English & Regional Languages**

Get Started Now

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पंचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसे HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) ने बनाया है। ₹ 79,450 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से बनी इस रिफाइनरी की कैपेसिटी 9 MMTPA है और यह पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को रिफाइनिंग के साथ जोड़ती है। यह प्रोजेक्ट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करता है, पेट्रोकेमिकल में आत्मनिर्भरता बढ़ाता है, साफ़ फ्यूल प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, रोज़गार पैदा करता है, और वैल्यू-एडेड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाता है, जो देश के एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ा मील का पत्थर है।
- जापान ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट के लिए अपना सपोर्ट फिर से पक्का किया है, जिसका टारगेट 2027 तक प्रायोरिटी सेक्शन पर कमर्शियल ऑपरेशन करना है। शिंकांसेन E10 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए 508 km के इस कॉरिडोर को JICA ने 0.1% इंटररेस्ट पर 50 साल के लोन के ज़रिए 81% फाइनेंस किया है। सूरत-बिलिमोरा/वापी के बीच पहला ऑपरेशनल हिस्सा 15 अगस्त 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि पूरा कॉरिडोर 2029 तक पूरा होने का टारगेट है। यह प्रोजेक्ट हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है और लंबे समय की इंडिया-जापान स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को मज़बूत करता है।
- ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA) ने नई दिल्ली में अपने पहले 15 ग्लोबल बायोफ्यूल चैंपियन फेलो को शामिल किया। 32 देशों से चुने गए हर फेलो को US\$15,000 तक की रिसर्च फंडिंग मिलेगी और वे दो साल तक GBA एंबेसडर के तौर पर काम करेंगे। G20 समिट 2023 के दौरान बनाए गए इस अलायंस में अब 34 देश और 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन शामिल हैं। यह फेलोशिप इथेनॉल, बायोडीज़ल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) में इनोवेशन को बढ़ावा देती है, रिसर्च में सहयोग, लीडरशिप डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करने वाले ग्लोबल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देती है।

राज्य समाचार

- महाराष्ट्र सरकार ने पालघर ज़िले के पास अरब सागर में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) के प्रपोज़्ड भारत के पहले ऑफ़शोर एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। प्रपोज़्ड उत्तान-विरार सी लिंक से लगभग 4.75 km दूर, इस एयरपोर्ट का मकसद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ज़मीन की कमी और बढ़ते एयर ट्रैफ़िक को कम करना है। इसमें वर्ल्ड-क्लास पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल होंगे, जिनमें आसान ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन और भविष्य में कैपेसिटी बढ़ाने की सुविधा होगी। इस प्रोजेक्ट से नॉइज़ पॉल्यूशन कम होने, ट्रेड, टूरिज़्म, लॉजिस्टिक्स, रोज़गार, रीजनल कनेक्टिविटी और महाराष्ट्र के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- राजस्थान और हरियाणा ने यमुना वॉटर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक अहम समझौते पर साइन किए, जिससे लगभग 30 साल पुराना पानी के बंटवारे का झगड़ा खत्म हो गया। लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) यमुना का पानी वेस्टर्न यमुना कैनाल से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के ज़रिए सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे पानी की

कमी वाले ज़िलों में पहुंचाया जाएगा। सेंट्रल वॉटर कमीशन के सपोर्ट वाले इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट-शेयरिंग, मॉनिटरिंग और झगड़े सुलझाने के तरीके शामिल हैं। इससे पीने के पानी की उपलब्धता बेहतर होगी, ग्राउंडवॉटर रिचार्ज को बढ़ावा मिलेगा, पानी की बर्बादी कम होगी, राज्यों के बीच सहयोग मज़बूत होगा और लंबे समय तक पानी की सुरक्षा बहेगी।

- दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने और हवा के प्रदूषण को कम करने के लिए ₹ 15,000 करोड़ के खर्च के साथ दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 (2026-2030) को मंजूरी दी है। यह पॉलिसी खरीदने पर सब्सिडी, ₹ 30 लाख तक की एलिजिबल EVs के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट, और आकर्षक स्कैपेज इंसेंटिव देती है। इसमें चुनी हुई कैटेगरी में नए पेट्रोल, डीज़ल और CNG गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर धीरे-धीरे रोक लगाने का भी प्रस्ताव है। लगभग 32,000 EV चार्जिंग स्टेशन और बढ़ा हुआ बैटरी-स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन मोबिलिटी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और कम कार्बन एमिशन में मदद करेगा।
- वेस्ट बंगाल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 29 जून 2026 को राज्य विधानसभा के बजट सेशन में पेश होने की उम्मीद है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 के आधार पर, यह शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने, गार्जियनशिप और उत्तराधिकार को कंट्रोल करने वाला एक कॉमन सिविल लॉ चाहता है, चाहे धर्म कुछ भी हो। प्रस्तावित प्रोविज़न में समान विरासत के अधिकार, एक से ज़्यादा शादी पर रोक, बाल विवाह को अमान्य करना और लिव-इन रिलेशनशिप का ज़रूरी रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। सपोर्टर इसे कानूनी बराबरी और जेंडर जस्टिस को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, जबकि आलोचक धार्मिक आज़ादी और फ़ेडरल सिद्धांतों की रक्षा पर ज़ोर देते हैं।
- ओडिशा कैबिनेट ने राज्य की ब्लू इकॉनमी को मज़बूत करने के लिए 2026-2036 के लिए ₹ 2,295.45 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी। फिशरीज़ एंड एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा लागू किए गए इस मिशन का मकसद समुद्री मछली पालन को मॉडर्न बनाना, डीप-सी में टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देना, सीफ़ूड एक्सपोर्ट में सुधार करना और रोज़ी-रोटी बढ़ाना है। इसका टारगेट 2036 तक सालाना 2 लाख मीट्रिक टन और मछली प्रोडक्शन, 50,000 नौकरियाँ बनाना और सीफ़ूड एक्सपोर्ट में ₹ 5,000 करोड़ कमाना है। एक प्रस्तावित ब्लू इकॉनमी हब (B-Hub) रिसर्च, इनोवेशन और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में मदद करेगा।
- असम के सोनितपुर ज़िले में बोरजुली साइट को जंगली चावल (ओरिज़ा रूफ़ीपोगोन) के इन-सीटू कंज़र्वेशन पर NRAA-फंडेड प्रोजेक्ट के बाद बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ़ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज़ (ICAR-NBPGR) ने असम स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के साथ मिलकर यह पहल की है, जिसका मकसद कीमती जंगली चावल के जर्मप्लाज़्म को बचाना है। NRAA के CEO डॉ. चंद्र शेखर कुमार के अनुसार, जंगली चावल क्लाइमेट-रेज़िलिएंट, ज़्यादा पैदावार वाली और न्यूट्रिशन के मामले में बेहतर चावल की किस्में डेवलप करने, सस्टेनेबल खेती और लंबे समय तक चलने वाली फूड सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए एक ज़रूरी जेनेटिक रिसोर्स है।

- गुजरात पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1-28 जुलाई 2026 तक 28 दिन का राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान, ऑपरेशन सुरक्षित साइबरस्पेस शुरू किया। DGP जीएस मलिक के नेतृत्व में, इस पहल का मकसद इंटेलेजेंस-लेड पुलिसिंग और पब्लिक जागरूकता के जरिए साइबरस्टॉकिंग, पहचान की चोरी, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन उत्पीड़न और प्राइवैसी के उल्लंघन को टारगेट करना है। बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों, स्कूलों, कॉलेजों, NGOs और RWAs के साथ मिलकर चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद 25 लाख नागरिकों को शिक्षित करना, 20 लाख छात्रों को जोड़ना, 10,000 स्कूलों, 1,500 कॉलेजों को कवर करना और महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
- गुजरात ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ₹ 190 करोड़ के बजट से IIT गांधीनगर में प्रोजेक्ट SAMARTH (सिलिकॉन एंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब) शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, गुजरात सरकार और IIT गांधीनगर के सपोर्ट से बने इस प्रोजेक्ट का मकसद पांच सालों में 10,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना है। यह हब L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशनस के साथ पार्टनरशिप के जरिए सेमीकंडक्टर रिसर्च, देसी चिप टेक्नोलॉजी, फैब ट्रेनिंग और इंडस्ट्री के लिए तैयार स्किल्स को बढ़ावा देगा, जिससे वर्कफोर्स डेवलपमेंट और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग में भारत के लक्ष्यों को सपोर्ट मिलेगा।
- दिल्ली सरकार ने BAT-BMS मोबाइल ऐप को हटाने और उसकी जांच करने का आदेश दिया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि यह असुरक्षित ब्लूटूथ-इनेबल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) के जरिए ई-रिक्शा को दूर से ही बंद कर सकता है। शेज़ेन ग्रेनेर्जी टेक्नोलॉजी का बनाया यह ऐप बैटरी पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, लेकिन कहा जाता है कि यह कमज़ोर ऑथेंटिकेशन की वजह से 15 मीटर के अंदर बिना इजाज़त के यूज़र्स को बैटरी डिस्चार्ज बंद करने देता था। अधिकारियों ने इस तरह के गलत इस्तेमाल को गैर-कानूनी बताया और पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी। यह घटना कनेक्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में साइबर सिक्योरिटी की कमज़ोरियों को दिखाती है और मजबूत ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पर ज़ोर देती है।
- सरकार ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की जलभरा संदेश, जनाई के मनोहरा और बालागढ़ लकड़ी की नावों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग दिए हैं। यह पहचान इन पारंपरिक प्रोडक्ट्स को कानूनी तौर पर नकल से बचाती है और साथ ही घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू को बढ़ाती है। जलभरा संदेश अपनी छिपी हुई गुलाब के स्वाद वाली चाशनी भरने के लिए जानी जाती है, मनोहरा अपनी चीनी से ढकी छेना मिठाई के लिए जानी जाती है, और बालागढ़ नावें 500 साल पुरानी नाव बनाने की परंपरा को दिखाती हैं। GI स्टेटस सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखता है, कारीगरों को सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, ब्रांडिंग को मजबूत करता है और गांवों में आजीविका को बेहतर बनाता है।

- हिमाचल प्रदेश ने आठ पारंपरिक उत्पादों के लिए GI पंजीकरण हासिल किया, जिससे इसके कुल GI-टैग वाले उत्पादों की संख्या 17 हो गई। नई मान्यता प्राप्त वस्तुओं में स्पीति सीबकथॉर्न, सलौनी सफेद मक्का, किन्नौरी सेब, किन्नौरी आभूषण, किन्नौरी टोपी, चंबा धातु कला, सेपुवाड़ी और सिरमौरी लोइया शामिल हैं। GI अधिनियम, 1999 के तहत दिए गए ये टैग प्रामाणिकता की रक्षा करते हैं, नकल को रोकते हैं, बाजार मूल्य में सुधार करते हैं, निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करते हैं। राज्य विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त कृषि और पारंपरिक उत्पादों के लिए GI मान्यता प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहा है।
- असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कमर्शियली माचा चाय का प्रोडक्शन किया है। इसका पहला बैच तिनसुकिया के छोटा टिंगराई टी एस्टेट में बनाया गया और गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर (GTAC) के जरिए नीलाम किया गया। जापानी एक्सपर्ट्स के साथ लगभग एक दशक के सहयोग के बाद डेवलप किया गया यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड जापानी प्रोसेसिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है। माचा, एक हाई-एंडीऑक्सीडेंट पाउडर वाली ग्रीन टी है, जो ब्लैक टी के अलावा असम की चाय इंडस्ट्री को भी अलग-अलग तरह की बनाती है। यह पहल स्पेशल चाय के एक्सपोर्ट को मजबूत करती है, इनोवेशन को बढ़ावा देती है, इंटरनेशनल मार्केट के मौकों को बढ़ाती है और भारत के प्रीमियम चाय सेक्टर को बढ़ाती है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- भारत और सऊदी अरब ने जेद्दा में सऊदी वॉटर वीक के दौरान वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल सिंचाई में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए। सुहेल खान और अब्दुलरहमान अब्दुलमोहसेन अलफदली द्वारा साइन किया गया यह एग्रीमेंट सिंचाई की कुशलता, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने को बढ़ावा देता है। यह क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण और बढ़ती मांग से पैदा होने वाली पानी की चुनौतियों को हल करता है। यह पार्टनरशिप एनर्जी और ट्रेड से आगे बढ़कर लंबे समय की वॉटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंस, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी और कोलेबोरेटिव रिसर्च को सपोर्ट करते हुए आपसी संबंधों को बढ़ाती है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे के दौरान, भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा, डिजिटल पेमेंट, हेल्थकेयर, स्पेस, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को मजबूत करने के लिए 19 समझौतों पर साइन किए। भारत ने एक स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी गाड़ियां, लेजर रेडियल सेलिंग बोट्स, एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया और PS जोरोस्टर को रिफिट किया। दोनों देशों ने UPI, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर में सहयोग बढ़ाया, जिसमें एक नया हॉस्पिटल भी शामिल है। भारत ने अपने MAHASAGAR विजन को फिर से पक्का किया और 500 टन चावल और 8,500 टन सीमेंट दिया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हुई।

- 26 जून 2026 को, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और लेबनान ने बॉर्डर पर तनाव कम करने और लंबे समय तक क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन किए। US की मध्यस्थता वाले इस एग्रीमेंट में धीरे-धीरे इजराइली मिलिट्री की फिर से तैनाती, लेबनानी आर्म्ड फोर्स (LAF) की ज्यादा तैनाती, हिज्बुल्लाह का वेरिफाइड डिसआर्मामेंट, पायलट सिक्योरिटी ज़ोन और US-समर्थित कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म शामिल है। इसमें लेबनान के लिए 100 मिलियन US डॉलर की मानवीय मदद भी शामिल है। जहाँ लेबनान और यूनाइटेड स्टेट्स ने इस पहल का स्वागत किया, वहीं इजराइल ने सेना की वापसी को हिज्बुल्लाह के डिसआर्मामेंट से जोड़ा, जबकि हिज्बुल्लाह ने इस एग्रीमेंट को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
- तारिक रहमान के बीजिंग दौर के दौरान चीन के साथ बातचीत के बाद बांग्लादेश के तीस्ता नदी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर ध्यान गया। इस प्रोजेक्ट में 140 मिलियन क्यूबिक मीटर सेडिमेंट की ड्रेजिंग, 171 sq km ज़मीन को फिर से बनाना, 234 km के तटबंध बनाना और उनकी मरम्मत करना, 224 km का रोड नेटवर्क बनाना और 82 जेट्टी बनाना शामिल है। क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है, इसलिए यह प्रोजेक्ट भारत-बांग्लादेश पानी के बंटवारे, रीजनल कनेक्टिविटी और बॉर्डर पार सहयोग के लिए स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। चीन ने किसी तीसरे देश को टारगेट किए बिना टेक्निकल सपोर्ट के तौर पर अपनी भूमिका पर ज़ोर दिया।
- प्रधानमंत्री साने ताकाइची के भारत दौर के दौरान भारत और जापान ने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को मज़बूत किया। दोनों देशों ने इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एनर्जी रेजिलिएंस पर एग्रीमेंट साइन किए, साथ ही सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ज़रूरी मिनरल, एडवांस्ड मटीरियल और रेजिलिएंट सप्लाय चैन को कवर करने वाला एक रोडमैप लॉन्च किया। उन्होंने ज़िम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली AI पार्टनरशिप की भी घोषणा की और GOBARdhan पहल के तहत लगभग 1,000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट लगाने की योजना बनाई। डिफेंस कोऑपरेशन, नेवल एक्सरसाइज और इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन को भी काफी बढ़ाया जाएगा।
- इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) और सेल्सफोर्स ने AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन शुरू किया है। इसका मकसद दुनिया भर में ज़िम्मेदार, सबको साथ लेकर चलने वाले और टिकाऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इस कमीशन में सरकारों, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के 40 से ज्यादा ग्लोबल लीडर शामिल हैं। भारतीय बिज़नेस लीडर मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी एन. मित्तल और विशाल तलवार इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, जो AI गवर्नेंस में भारत के बढ़ते असर को दिखाता है। पॉल कागामे और डोरेन बोगदान-मार्टिन के वाइस-चेयरमैन के साथ, यह कमीशन AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2026 के दौरान बातचीत शुरू करेगा।
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO) ने बुडिबुग्यो इबोला वायरस के लिए पहला मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट अपनी इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग (EUL) में जोड़ा है, जिससे बीमारी फैलने पर लैब में तेज़ी से कन्फर्मेशन हो सकेगा। यह टेस्ट ब्लड सैंपल में वायरल RNA का पता लगाता है,

जिससे ज़ैरे इबोलावायरस से अलग स्ट्रेन का डायग्नोसिस बेहतर होता है। 2007 में युगांडा में पहली बार पहचाने गए इस वायरस ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (DRC) में बड़ा आउटब्रेक किया है। यह नया डायग्नोस्टिक आउटब्रेक की तैयारी को मज़बूत करता है, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, और वायरल हैमरेजिक फीवर और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के खिलाफ ग्लोबल रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है।

- भारत और माली ने बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए बमाको में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पहला इंडिया-माली फोरम लॉन्च किया। FY 2025-26 में बाइलेटरल ट्रेड US\$326.61 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें भारत की DFTP स्कीम से 55% की ग्रोथ हुई। फोरम में B2B, B2G और G2G मीटिंग हुई, जिनमें टेक्सटाइल, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, डिजिटल ट्रेड और एग्रो-इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। माली ने दिसंबर 2026 के लिए एक इन्वेस्टमेंट फोरम की भी घोषणा की, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट के मौकों और लंबे समय के इकोनॉमिक सहयोग को मज़बूत करेगा।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (IIP) मई 2026 में 5.1% बढ़ा, जो पांच महीनों में इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि गर्मियों की डिमांड और रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन की वजह से बिजली और गैस सप्लाय में 9.9% की बढ़ोतरी हुई। कैपिटल गुड्स का आउटपुट 12.9% बढ़ा, जो मज़बूत इन्वेस्टमेंट दिखाता है, जबकि माइनिंग में कमी आई। रिलीज़ में 2022-23 बेस ईयर बताया गया और इंडस्ट्रियल आउटपुट को बेहतर तरीके से मापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) की जगह आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) को लाया गया। ये आंकड़े मज़बूत होती इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक रिकवरी को दिखाते हैं।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के मुताबिक, FY26 के आखिर में भारत का बाहरी कर्ज बढ़कर \$762.8 बिलियन हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले \$26.3 बिलियन ज्यादा है। बाहरी कर्ज-से-GDP रेश्यो 19.8% से बढ़कर 20.8% हो गया। US डॉलर के मज़बूत होने से रिपोर्ट की गई बढ़ोतरी \$24.6 बिलियन कम हो गई। कर्ज अभी भी अलग-अलग तरह का है, जिसमें US डॉलर का हिस्सा सबसे ज्यादा है, उसके बाद भारतीय रुपया, जापानी येन और यूरो का नंबर आता है। मज़बूत फॉरिन एक्सचेंज रिज़र्व पूरे बाहरी सेक्टर की स्थिरता को सपोर्ट करता रहता है।
- यूरोबैंक ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ मिलकर ग्रीस के कस्टमर्स को तुरंत भारत में पैसे ट्रांसफर करने में मदद करने वाली UPI-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस सर्विस शुरू की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पहल का स्वागत किया, और कम ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और मज़बूत डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी पर ज़ोर दिया। अपने ग्रीस दौर के दौरान, उन्होंने इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए यूरोबैंक के CEO फोकियन करावियास से भी मुलाकात की। यह पहल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की ग्लोबल पहुंच को बढ़ाती है, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, आसान रेमिटेंस को बढ़ावा देती है, और डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में भारत की लीडरशिप को मज़बूत करती है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, FY26 के आखिर तक भारत का बाहरी कर्ज़ बढ़कर \$762.8 बिलियन हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले \$26.3 बिलियन ज़्यादा है, और कर्ज़-से-GDP रेश्यो बढ़कर 20.8% हो गया। US डॉलर के मज़बूत होने से रिपोर्ट की गई बढ़ोतरी \$24.6 बिलियन कम हो गई, जबकि कर्ज़ की बनावट US डॉलर, भारतीय रुपया, जापानी येन और यूरो में अलग-अलग तरह की रही। कम समय के उधार में तेज़ी से बढ़ोतरी के बावजूद, भारत के मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार ने पूरे बाहरी सेक्टर में लचीलापन और स्थिरता बनाए रखी है।
- HDFC बैंक ने पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को तीन साल के लिए अपना पार्ट-टाइम चेयरमैन बनाया है, जो RBI की मंजूरी पर निर्भर है। उन्हें 30 जून 2026 से चार साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनाया गया है, जो शेयरहोल्डर की मंजूरी पर निर्भर है। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद वह अंतरिम व्यवस्था की जगह लेंगे, जबकि केकी मिश्री मंजूरी पूरी होने तक अंतरिम चेयरमैन बने रहेंगे। 1984 बैच के IAS ऑफिसर, राजीव कुमार पहले डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। गवर्नंस, बैंकिंग सुधारों और पब्लिक फाइनेंस में उनकी एक्सपर्टीज़ से कॉर्पोरेट गवर्नंस के मज़बूत होने की उम्मीद है।
- ओपनAI ने उबर इंडिया और साउथ एशिया के पूर्व प्रेसिडेंट प्रभजीत सिंह को सितंबर 2026 से भारत के लिए अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। किरण मणि को रिपोर्ट करते हुए, वे भारत के तेज़ी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन्स, पार्टनरशिप्स और एक्सपेंशन की देखरेख करेंगे। टेक्नोलॉजी बिज़नेस को बढ़ाने और उबर की ग्रोथ को लीड करने का सिंह का अनुभव उन्हें इस रोल के लिए एकदम सही बनाता है। उनका अपॉइंटमेंट भारत के बड़े डिजिटल यूज़र बेस, बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम, बढ़ते एंटरप्राइज़ AI एडॉप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सरकार के मज़बूत फोकस की वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत को दिखाता है, जिससे देश में ओपनAI के लॉन्ग-टर्म एक्सपेंशन प्लान्स मज़बूत होंगे।
- नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) के अनुसार, भारत की बेरोज़गारी दर 2025 में घटकर 3.1% हो जाएगी, जो आठ सालों में सबसे कम है। यह बेहतर रोज़गार, आर्थिक सुधार और लेबर फ़ोर्स में भागीदारी में बढ़ोतरी को दिखाता है। यह सुधार 2030 तक प्रोडक्टिव रोज़गार को टारगेट करने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को सपोर्ट करता है। हालांकि शहरी महिलाओं की बेरोज़गारी 2017-18 में 10.8% से घटकर 2025 में 6.4% हो गई, लेकिन बिहार, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बेरोज़गारी की दर लगातार बढ़ रही है। गुजरात में जेंडर में काफ़ी समानता देखी गई, जबकि केरल और महाराष्ट्र में भी काफ़ी सुधार हुआ।
- कंट्रोलर जनरल ऑफ़ अकाउंट्स (CGA) के अनुसार, भारत का फिस्कल डेफिसिट अप्रैल-मई FY2026-27 के दौरान बढ़कर ₹ 1.62 लाख करोड़ हो गया, जो सालाना बजट अनुमान ₹ 16.96 लाख करोड़ का 9.6% है। कुल रिसीट घटकर ₹ 7.19 लाख करोड़ रह गई, जिसका मुख्य कारण कमज़ोर टैक्स कलेक्शन और फ्यूल टैक्स में कटौती के बाद एक्साइज़ ड्यूटी में लगभग 20% की गिरावट है। सरकारी खर्च 18% बढ़कर ₹ 8.81 लाख करोड़ हो गया, जबकि कैपिटल खर्च 13% से ज़्यादा बढ़ा। RBI के ₹ 2.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड डिविडेंड ने डेफिसिट को कुछ हद तक कम किया।
- जून 2026 में भारत का ग़्रॉस GST कलेक्शन ₹ 1,94,812 करोड़ तक पहुँच गया, जो सालाना 13.9% की बढ़ोतरी है, जबकि रिफंड के बाद नेट GST कलेक्शन ₹ 1,62,377 करोड़ रहा, जो 11.2% ज़्यादा है। इम्पोर्ट से जुड़ा GST 34.6% बढ़कर ₹ 60,038 करोड़ हो गया, जो ग्रोथ का मुख्य कारण बना, जबकि घरेलू कलेक्शन 6.5% बढ़ा। रिफंड 29.1% बढ़कर ₹ 32,436 करोड़ हो गया। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात का नंबर रहा, जबकि सिक्किम, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु ने GST रेवेन्यू में गिरावट की जानकारी दी।
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने 1 जुलाई 2026 को नौ साल पूरे कर लिए हैं, जो भारत के "एक राष्ट्र,
- 2017 में "वन टैक्स" सुधार शुरू किया गया। GST ने कई इनडायरेक्ट टैक्स की जगह ली, एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाया, कैस्केडिंग टैक्सेशन कम किया और डिजिटल सिस्टम के ज़रिए कम्प्लायंस को बेहतर बनाया। GST 2.0 ने लगज़री और सिन गुड्स के लिए आसान 5%, 18% और 40% टैक्स स्लैब पेश किए, साथ ही रजिस्ट्रेशन, रिफंड और रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाया। रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 66.5 लाख से बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई, जो ज़्यादा फॉर्मलाइज़ेशन, ट्रांसपेरेंसी और मज़बूत रेवेन्यू कलेक्शन को दिखाता है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने HSBC इंडिया और JP मॉर्गन पेमेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसके तहत क्रॉस-बॉर्डर UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए रियल-टाइम फॉरेन एक्सचेंज (FX) कन्वर्ज़न और सेटलमेंट शुरू किया गया है। यह सिस्टम तुरंत करेंसी कन्वर्ज़न, तेज़ पेमेंट कन्फ़र्मेशन, रियल-टाइम सेटलमेंट और ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज रेट देता है, साथ ही बिचौलियों और सेटलमेंट में देरी को भी कम करता है। यह पहल इंटरनेशनल पेमेंट में सिक्योरिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफ़िशिएंसी को बेहतर बनाती है। क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट की बड़ी चुनौतियों को हल करके, यह पार्टनरशिप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की ग्लोबल पहुँच को बढ़ाती है और डिजिटल पेमेंट इनोवेशन में भारत की लीडरशिप को मज़बूत करती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई 2026 से "एक देश, एक लोकपाल" के सिद्धांत के तहत 2021 के फ्रेमवर्क की जगह, नई इंटीग्रेटेड लोकपाल स्कीम लागू की। यह स्कीम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, योग्य NBFCs, प्रीपेड पेमेंट इस्ट्रूमेंट जारी करने वालों और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को कवर करते हुए एक मुफ्त, तेज़ और पारदर्शी शिकायत निवारण सिस्टम देती है। अगर 30 दिनों के बाद भी शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक RBI से संपर्क कर सकते हैं। यह ऑनलाइन फाइलिंग, बिना विरोध के विवाद समाधान और फाइनेंशियल नुकसान के लिए ₹ 30 लाख तक और परेशानी के लिए ₹ 3 लाख तक का मुआवज़ा देती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जुलाई 2026 से रवि शंकर को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले वे डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट (DSIM) के एडवाइजर-इन-चार्ज के तौर पर काम कर रहे थे। उनके पास बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेटलमेंट सिस्टम, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक रिसर्च में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने मैक्रोइकॉनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल सेक्टर एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसी और डेटा गवर्नंस पर RBI की कई कमेटियों में योगदान दिया है, जो उनकी एक्सपर्टीज़ और लीडरशिप पर सेंट्रल बैंक के भरोसे को दिखाता है।

- स्टील मंत्रालय ने MECON लिमिटेड को मिनिस्टर कैटेगरी-I का दर्जा दिया है, जिससे उसके लगातार प्रॉफिट और ऑपरेशनल एक्सीलेंस को पहचान मिली है। 1959 में शुरू हुई और इसका हेडक्वार्टर रांची, झारखंड में है। MECON एक शेड्यूल 'A' सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस देता है। कंपनी ने लगातार तीन फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के बाद 31 मार्च 2026 तक ₹ 535.42 करोड़ की नेट वर्थ हासिल की। नया स्टेटस ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, जिससे तेज़ी से फैसले लेने, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन, बिजनेस बढ़ाने और मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में मदद मिलती है।
- माइक्रोसॉफ्ट और लाइटस्टॉर्म ने I-2SEA (भारत-2-दक्षिण पूर्व एशिया) अंडरसी केबल विकसित करने के लिए भागीदारी की, जो भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ने वाला 3,600 किलोमीटर का सबमरीन फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क है। इस कंसोर्टियम में टाटा कम्युनिकेशंस, सिंगटेल, आसियान केबलशिप और एनईसी कॉर्पोरेशन शामिल हैं, जिसका लैंडिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में है। Q4 2029 तक चालू होने की उम्मीद है, यह केबल AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाइपरस्केल डेटा सेंटर और उच्च क्षमता वाली डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। पनडुब्बी केबलों के माध्यम से प्रसारित 95% वैश्विक इंटरनेट यातायात का हिस्सा वहन करते हुए, यह क्षेत्रीय डिजिटल लचीलापन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- केंद्र सरकार ने कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC) से मंजूरी मिलने के बाद, रवि अग्रवाल को 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक छह महीने के एक्स्ट्रा टर्म के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) का चेयरमैन फिर से अपॉइंट किया है। 1988 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर, वे जून 2024 से CBDT चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत CBDT, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो टैक्स पॉलिसी, इनकम-टैक्स एक्ट को लागू करने, कम्प्लायंस, ट्रांसपेरेंसी और टैक्स चोरी से निपटना।
- इंडियन REITs एसोसिएशन (IRA) ने नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट के CEO शिरीष गोडबोले को आलोक अग्रवाल की जगह अपना नया चेयरपर्सन बनाया है। SEBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री के गाइडेंस में 2023 में बना IRA, इंडिया के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। गोडबोले ने गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर अवेयरनेस और सस्टेनेबल सेक्टर ग्रोथ को मजबूत करने का वादा किया। सत्व ग्रुप और ब्लैकस्टोन के सपोर्ट वाला नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा लिस्टेड REIT है।
- भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से एक साल के लिए बढ़ा दिया है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी, वे 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव बने। तीन दशकों से ज्यादा के

डिप्लोमैटिक अनुभव के साथ, उन्होंने ब्रुसेल्स, ट्यूनिंस, इस्लामाबाद, वाशिंगटन DC, श्रीलंका, म्यूनिख और स्पेन, म्यांमार और चीन में राजदूत के तौर पर काम किया है। उन्होंने 2022 और 2024 के बीच डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (स्ट्रेटेजिक अफेयर्स) के तौर पर भी काम किया।

- AGMUT कैडर के 2001 बैच के IAS ऑफिसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC) से मंजूरी मिलने के बाद, गृह मंत्रालय के गृह विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया गया। वे रेगुलर अपॉइंटमेंट होने तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के चेयरपर्सन के तौर पर एडिशनल चार्ज के साथ काम करते हुए बड़ी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को देखेंगे। यह अपॉइंटमेंट एजुकेशन और इंटरनल गवर्नेंस में उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव पर सरकार के भरोसे को दिखाता है।

रक्षा समाचार

- जनरल धीरज सेठ ने 30 जून 2026 को 31वें चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ (COAS) का पद संभाला, वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। इससे पहले वे 49वें वाइस चीफ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से ग्रेजुएशन करने के बाद दिसंबर 1986 में आर्मीड कॉर्प्स में कमीशन मिला था। लगभग चार दशकों की सर्विस में, उन्होंने अहम फ़ॉर्मेशन की कमान संभाली है और 1997 में जनरल शंकर राय चौधरी के बाद आर्मी चीफ बनने वाले पहले आर्मीड कॉर्प्स ऑफिसर बने।
- पोर्ट और शिप सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मिनिस्ट्री के तहत ब्यूरो ऑफ़ पोर्ट सिक्योरिटी (BoPS) बनाया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) के तहत काम करने वाला और BCAS की तरह, BoPS सर्विलांस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी, कम्प्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट की देखरेख करेगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स (CISF) सिक्योरिटी असेसमेंट करेगा, सिक्योरिटी प्लान तैयार करेगा और ट्रेनिंग देगा। यह पहल भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मॉडर्न बनाती है और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिजिकल और साइबर खतरों से सुरक्षा को मजबूत करती है।
- प्रोजेक्ट ब्रह्मक, बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) की एक खास पहल है। इसने अरुणाचल प्रदेश में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया, जो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पंद्रह साल पूरे होने का जश्न है। 2011 से, इसने मुश्किल हिमालयी इलाकों में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और खास पुल बनाए और उनकी देखभाल की है। इस प्रोजेक्ट ने दूर-दराज के इलाकों में बॉर्डर कनेक्टिविटी, मिलिट्री मोबिलिटी, आपदा से निपटने की क्षमता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाया है। बॉर्डर इलाकों में हर मौसम में पहुंच देकर, यह भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है और साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए हेल्थकेयर, शिक्षा और ज़रूरी सेवाओं में सुधार करता है।

- रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस रिसर्च की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए DRDO को फाइनेंशियल पावर्स का डेलीगेशन 2026 (DFP-2026) पेश किया। यह फ्रेमवर्क डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) के अलग-अलग लेवल पर ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, जिससे प्रोक्वोरमेंट, रिसर्च, इनोवेशन और टेस्टिंग के लिए तेज़ी से अप्रूवल मिल पाते हैं। यह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF), एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च (EMR), और डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर जैसे प्रोग्राम को मज़बूत करता है। यह रिफॉर्म प्रोसेस में होने वाली देरी को कम करता है, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, MSMEs, एकेडेमिया के साथ कोलेबोरेशन को बढ़ावा देता है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करता है।
- भारत ने 27 जून 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक (इंडियन कोस्ट गार्ड) बेड़े में नई पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) ICGS अक्षय को शामिल किया। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित, इस पोत को तटीय निगरानी, समुद्री कानून प्रवर्तन, खोज और बचाव, तस्करी विरोधी अभियानों, आपदा प्रतिक्रिया और पर्यावरण संरक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। संस्कृत शब्द "अक्षय" जिसका अर्थ अविनाशी है, के नाम पर रखा गया यह पोत भारत के 7,500 किलोमीटर के समुद्र तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाता है। यह पोत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए समुद्री अपराध से निपटने की भारत की क्षमता को मज़बूत करता है।
- इंडियन आर्मी 1 जुलाई 2026 को पानागढ़ में XVII कॉर्प्स (माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स) के तहत अपने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) को ऑपरेशनलाइज़ करेगी। हर IBG एक ब्रिगेड के साइज़ का, सेल्फ-सफिशिएंट फॉर्मेशन है जिसमें 5,000 से ज़्यादा सैनिक होंगे, जिसमें एक मेजर जनरल के अंडर इन्फैंट्री, आर्टिलरी, आर्मेड, इंजीनियर, एयर डिफेंस, सिग्नल, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सपोर्ट इंटीग्रेट होंगे। 48 घंटे के अंदर डिप्लॉयमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया यह कॉन्सेप्ट जनरल बिपिन रावत ने प्रपोज़ किया था और एक्सरसाइज़ हिमविजय (2019) के दौरान टेस्ट किया गया था। यह रिफॉर्म मल्टी-डोमेन वॉरफेयर के लिए भारत की तैयारी को काफी बढ़ाता है, खासकर भारत-चीन बॉर्डर पर।
- वैं आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने टेक्नोलॉजी से चलने वाली, भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना बनाने के लिए VIJAY विज़न पेश किया। यह फ्रेमवर्क विजिलेंस और रेडीनेस, इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भरता और योद्धा फर्स्ट पर फोकस करता है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन, स्वदेशी डिफेंस कैपेबिलिटी और सैनिक वेलफेयर पर ज़ोर दिया गया है। लगभग चार दशकों की सर्विस के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र, जनरल सेठ का लक्ष्य मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में तेज़ी लाना, तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन को मज़बूत करना और आर्मी को विकसित भारत 2047 के नेशनल विज़न के साथ जोड़ना है।
- K9 वज्र-T स्व-चालित होवित्जर कार्यक्रम मेक इन इंडिया के तहत भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को उजागर करता है। हनवा एयरोस्पेस और लार्सन एंड टूब्रो (L&T) के बीच सहयोग के माध्यम से विकसित, 155 मिमी/52-कैलिबर तोपखाना प्रणाली 50-60% स्वदेशी सामग्री के साथ गुजरात के हजीरा में निर्मित होती है। भारत ने 2021 तक 100 इकाइयां शामिल कीं, 2024 में अन्य 100

का आदेश दिया, और ₹ 23,000 करोड़ के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 300 अतिरिक्त तोपों की योजना है। यह प्रणाली चुनौतीपूर्ण इलाकों में लंबी दूरी की तोपखाने की क्षमता और सीमा की तैयारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।

- एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, एवीएसएम, वीएसएम, ने 1 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) के रूप में पदभार ग्रहण किया, वे एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लेंगे। 1989 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त, वे एक पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्होंने अपाचे, मिग-21, जगुआर, मिग-29, एसयू-30 और राफेल सहित विमानों पर 3,000 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने पहले सहायक वायुसेनाध्यक्ष (ऑपरेशंस-आक्रामक), महानिदेशक (हथियार प्रणाली) और वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में कार्य किया,
- एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (VCAS) का पद संभाला। 1986 में कमीशन प्राप्त एक फाइटर पायलट, उन्होंने 20 से ज़्यादा तरह के एयरक्राफ्ट पर 3,300 से ज़्यादा फ्लाईंग घंटे जमा किए हैं। उनके शानदार करियर में मिराज-2000 स्क्वाड्रन, एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस की कमान संभालना, और एयर डिफेंस कमांडर, डायरेक्टर ऑफ एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (CISC) के तौर पर काम करना शामिल है। साथ ही, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने नए CISC का पद संभाला।
- लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, AVSM, VSM, ने 1 जुलाई 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन की जगह लेते हुए सदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) का पद संभाला। नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र, 1988 में 74 आर्म्ड रेजिमेंट में कमीशन हुए, उनके पास लगभग चार दशकों की मिलिट्री सर्विस है। उन्होंने एक आर्म्ड रेजिमेंट, इंडिपेंडेंट आर्म्ड ब्रिगेड, इन्फैंट्री डिवीजन और 2 कोर (खरगा कोर) की कमान संभाली है। पुणे में हेडक्वार्टर वाली सदर्न कमांड, दक्षिणी और मध्य भारत में ऑपरेशनल तैयारी, लॉजिस्टिक्स, आपदा राहत और डिफेंस की देखरेख करती है।
- एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CISC) के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ का चार्ज संभाला। नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद, उन्हें सेरेमोनियल ट्राई-सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर मिला। 1987 में इंडियन एयर फोर्स में कमीशन हुए, वे कैटेगरी 'A' क्वालिफाइड फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर हैं, जिनके पास 4,500 से ज़्यादा फ्लाईंग घंटे हैं। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, रडार स्टेशन, फाइटर बेस और जम्मू और कश्मीर एयर कमांड को कमांड किया है, और उन्हें वायु सेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं।
- इंडियन नेवी ने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज़ RIMPAC 2026 के लिए हवाई में एक P-8I लंबी दूरी का समुद्री टोही और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट तैनात किया है। US पैसिफिक फ्लीट की होस्ट की हुई यह एक्सरसाइज़ 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक चलेगी, जिसमें 30 से ज़्यादा देश, वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और लोग शामिल होंगे। भारत 2014 से इसमें हिस्सा ले रहा है, जिससे इंडो-पैसिफिक में समुद्री सहयोग मज़बूत हुआ है। यह तैनाती सर्विलांस, एंटी-सबमरीन क्षमताओं, इंटरऑपरेबिलिटी, क्लेक्टिव रेडीनेस को मज़बूत करती है और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक विज़न को सपोर्ट करती है।

- डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने भारत की आर्म्ड फोर्सों को मॉडर्न बनाने और स्वदेशी क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए ₹ 52,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। ये मंजूरीयां आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स में ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाते हुए एडवांस्ड डिफेंस इन्फ्रस्ट्रक्चर की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करती हैं। प्रोक्योरमेंट पैकेज कॉम्बैट रेडीनेस, टेक्नोलॉजी इंडक्शन, सेल्फ-रिलायंस, डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। यह फैसला स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देता है, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करता है, और भारत के लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटिजिक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान्स के तहत मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन को तेज़ करता है।

पुरस्कार और सम्मान

- भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को वाशिंगटन, DC में अपने सालाना लीडरशिप समिट के दौरान US-इंडिया स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) से 2026 का लीडरशिप अवॉर्ड मिला। यह सम्मान भारत-US के आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करने और भारत के टेक्नोम्युनिकेशन सेक्टर को बदलने में उनके शानदार योगदान को पहचान देता है। मित्तल ने डिजिटल कनेक्टिविटी, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट के महत्व पर जोर दिया, साथ ही प्रस्तावित भारत-US ट्रेड एग्रीमेंट के जल्द पूरा होने का भरोसा जताया। यह अवॉर्ड दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव बिजनेस और दो-तरफ़ा कर्मशियल सहयोग को बढ़ावा देने में उनके रोल को भी पहचान देता है।
- 2027 से, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का नाम बदलकर बुखमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कर दिया जाएगा। यह बुखमैन फिलैंथ्रोपीज़ के साथ 10 साल की पार्टनरशिप के तहत होगा। सालाना प्राइज़ मनी दोगुनी होकर £100,000 हो जाएगी, जो लेखक और ट्रांसलेटर के बीच बराबर बांटी जाएगी, जबकि शॉर्टलिस्ट की गई एंट्रीज़ में से हर एक को £5,000 मिलते रहेंगे। डारिया और दिमित्री बुखमैन द्वारा शुरू किया गया यह परोपकारी संगठन साहित्य, शिक्षा और हेल्थकेयर को सपोर्ट करता है। 2027 में केटी कितामुरा की अध्यक्षता में, यह अवॉर्ड UK या आयरलैंड में पब्लिश हुए बेहतरीन ट्रांसलेटेड फिक्शन को पहचान देना जारी रखेगा।

शिखर सम्मेलन और कार्यक्रम

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में “इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: विकसित भारत के लिए भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना” विषय पर ASSOCHAM के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ट्रांज़िशन में ग्रीन ग्रोथ, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और सर्कुलर इकॉनमी को प्राथमिकता देनी चाहिए। चर्चा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी सप्लाय चैन, लोकलाइज़ेशन, फाइनेंसिंग और इनोवेशन शामिल थे। मंत्री ने PARIVESH पोर्टल, बैटरी रीसाइक्लिंग, ज़रूरी मिनरल सिक्योरिटी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, जिससे विकसित भारत 2047 विज़न के तहत क्लीन मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनने की भारत की इच्छा को बल मिला।

खेल समाचार

- किदांबी श्रीकांत ने US ओपन 2026 में पुरुषों के सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, और चीनी ताइपे के सु ली-यांग के बाद दूसरे नंबर पर रहे। पहला गेम 15-21 से हारने के बाद, श्रीकांत ने वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-16 से जीता, लेकिन आखिर में 9-21 से हार गए। यह परफॉर्मेंस हाल के सालों में उनके सबसे अच्छे इंटरनेशनल नतीजों में से एक है और इससे भविष्य के BWF टूर्नामेंट से पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उनका आखिरी BWF टाइटल 2017 फ्रेंच ओपन में आया था, और वह एक और चैंपियनशिप जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
- क्रिकेट एक सदी से भी ज़्यादा समय के बाद लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक गेम्स (LA28) में पुरुषों और महिलाओं के T20 टूर्नामेंट के साथ वापस आएगा, जिसमें हर टूर्नामेंट में छह टीमें होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ICC रैंकिंग, कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंटेशन, होस्ट देश की एलिजिबिलिटी और 2027 ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के आधार पर एक क्वालिफिकेशन सिस्टम की घोषणा की है। चार महिला टीमें—ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन—पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। ओलंपिक में वापसी से क्रिकेट की ग्लोबल पहुंच बढ़ने, नए दर्शकों को आकर्षित करने और इसकी इंटरनेशनल प्रोफाइल को मज़बूत करने की उम्मीद है।
- इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेंट ब्रिज में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ तीसरे टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिससे उनके 15 साल के शानदार करियर का अंत हो गया। वह इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान का पद भी छोड़ देंगे, यह पद अप्रैल 2022 से था। स्टोक्स को 2019 ICC वर्ल्ड कप फ़ाइनल में मैच जिताने वाली 84 रन की पारी और 2019 एशेज़ के दौरान हेडिंग्ले में शानदार 135 रन के लिए याद किया जाता है। उनका सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ 258 रन है। कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ, उन्होंने आक्रामक बाज़बॉल सोच के ज़रिए इंग्लैंड के टेस्ट अप्रोच को बदल दिया।
- केरल की एंसी सोजन ने भुवनेश्वर में 2026 नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बाबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। 22 साल का नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड। 25 साल की इस खिलाड़ी ने 6.88 मीटर की छलांग लगाई, जो 2004 में बनाए गए 6.83 मीटर के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है। केरल को रिप्रेजेंट करते हुए और इंडियन नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल की। एंसी ने इससे पहले 2023 एशियन गेम्स और 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते थे, जिससे वह इंडिया के टॉप फील्ड एथलीट्स में शामिल हो गईं।
- इंडोनेशिया ने अहमदाबाद में कोरिया को हराकर अपना पहला AVC मेन्स वॉलीबॉल कप 2026 का खिताब जीता। पहले ग्रुप-स्टेज की हार से उबरकर फाइनल में 3-0 से जीत हासिल की। बाँय अर्नेज़ अरबी ने 17 पॉइंट्स बनाए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) अवॉर्ड जीता, और ड्रीम टीम में जगह बनाई। कोरिया ने अपना पहला सिल्वर मेडल जीता, जबकि मेज़बान भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन बहरीन को हराकर ऐतिहासिक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। 3-1 से हराया। इंडोनेशिया के शानदार प्रदर्शन ने FIVB वर्ल्ड रैंकिंग में भी उसकी स्थिति 52वें से 43वें स्थान पर पहुंचा दी, जो टूर्नामेंट में उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

- जॉर्ज रसेल ने रेड बुल रिंग में 2026 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता, पोल पोर्जीशन को अपनी सातवीं फॉर्मूला 1 जीत में बदला और मर्सिडीज की चैंपियनशिप चुनौती को मजबूत किया। उन्होंने मैक्स वेरस्टैपेन को पीछे छोड़ा, जो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चैंपियनशिप लीडर किमी एंटेनेली ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे उनकी बढ़त 40 पॉइंट हो गई। कार्लोस सैन्ज़ के रिटायरमेंट और कई टेक्निकल रिटायरमेंट के बाद रेस में एक वर्चुअल सेफ्टी कार शामिल थी। रसेल की जीत ने उन्हें चैंपियनशिप स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जिससे मर्सिडीज, रेड बुल और मैकलारेन के बीच 2026 फॉर्मूला 1 टाइटल की लड़ाई और तेज हो गई।
- स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में वर्ल्ड रोइंग कप 2026 में भारत ने इतिहास रच दिया, जब इंडियन आर्मी के हवलदार लक्ष्य और उज्ज्वल कुमार सिंह ने लाइटवेट मेन्स डबल स्कल्स (LM2x) इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने 6:26.09 का समय निकाला, और हांगकांग और नीदरलैंड्स के कॉम्पिटिटर्स को बहुत कम अंतर से हराया। पुणे के आर्मी रोइंग नोड में ट्रेनिंग लेने वाले, उन्होंने वीजा अप्रूवल में देरी और तैयारी के कम समय को पार किया। उनकी जीत इंडियन रोइंग के लिए एक बड़ी कामयाबी है और यह एलीट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में आर्म्ड फोर्स के योगदान को दिखाती है।
- इंग्लैंड की तेज़ गेंदबाज़ लॉरेन बेल ने मई 2026 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवॉर्ड जीता, और यह सम्मान पहली बार हासिल किया। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ़ शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने नॉमिनी मैडी ग्रीन और गुल फ़िरोज़ा से बेहतर प्रदर्शन किया। बेल ने ODI सीरीज़ में पाँच विकेट लिए, जिसमें 3/20 शामिल हैं, और चार T20I में लगातार इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए। उनकी असरदार बॉलिंग ने इंग्लैंड के पेस अटैक को मजबूत किया और विमेंस T20 वर्ल्ड कप सहित बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से पहले उनकी बढ़ती अहमियत को दिखाया।
- बांग्लादेश के बैटर मुशफ़िकुर रहीम को पाकिस्तान के खिलाफ़ शानदार परफॉर्मेंस के बाद मई 2026 के लिए ICC मेन्स प्लेयर ऑफ़ द मंथ का अवॉर्ड मिला। उन्होंने 63.25 की एवरेज से 253 रन बनाए, जिससे बांग्लादेश ने टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से ऐतिहासिक जीत हासिल की और प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड जीता। उनकी खास पारियों में पहले टेस्ट में 71 और दूसरे टेस्ट में सिलहट में 137 रन शामिल हैं। यह उनका दूसरा ICC मंथली अवॉर्ड था, जिससे बांग्लादेश की सफलता और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिए उनकी अहमियत और पक्की हो गई।
- भारतीय पैरा-एथलीट होकाटो होटोवे सेमा 2 जुलाई 2026 को पुरुषों की शॉट पुट F57 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बन गए। 9 असम रेजिमेंट में सूबेदार और पेरिस 2024 पैरालंपिक ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट, उन्होंने 14.65 मीटर का पर्सनल बेस्ट श्रो हासिल किया। सेमा अति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले पहले पैरालंपियन हैं और उन्हें अर्जुन अवॉर्ड भी मिला है। 2002 में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में अपना पैर गंवाने के बाद, वह अपने ज़बरदस्त पकड़े इरादे और इंटरनेशनल सफलता से भारत के जाने-माने पैरा-एथलीटों में से एक बन गए।

- क्रिस्टियानो रोनाल्डो FIFA वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 41 साल और 147 दिन की उम्र में क्रोएशिया के खिलाफ गोल किया। उनकी पेनल्टी ने पुर्तगाल को 2-1 से जीत दिलाई और राउंड ऑफ़ 16 के लिए क्वालिफ़ाई किया, जहाँ उनका सामना स्पेन से होगा। यह गोल 2006 में डेब्यू करने के बाद उनका पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल था। रोनाल्डो वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच शुरू करने वाले सबसे उम्रदराज आउटफ़ील्ड खिलाड़ी भी बन गए और 26 वर्ल्ड कप मैचों के साथ लोथर मैथॉस के रिकॉर्ड के करीब पहुँच गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- ISRO ने 24 जून 2026 को महेंद्रगिरी के ISRO प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (IPRC) में अपने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA) का आठवां हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। इंजन ने 175 टन थ्रस्ट पैदा किया, जो इसकी तय 200 टन क्षमता का लगभग 88% है, जिससे प्री-बर्नर, टर्बोपंप और प्रोपेलेंट फीड सिस्टम जैसे ज़रूरी सिस्टम को वैलिडेट किया गया। लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और इसरोसीन से चलने वाला SE2000 इंजन LVM3 लॉन्च व्हीकल के SC120 स्टेज को आगे बढ़ाएगा। इस कामयाबी से पेलोड क्षमता, फ्यूल एफिशिएंसी, स्वदेशी क्षमता और गगनयान, चंद्रयान और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च जैसे भविष्य के मिशन को बढ़ावा मिलेगा।
- ब्रेकीबैक्टीरियम नेताजी एक नई खोजी गई बैक्टीरिया की प्रजाति है जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से अलग किया गया है। पॉलीफेसिक टैक्सोनॉमिक विशेषताओं से पहचाना गया यह बैक्टीरिया पी-नाइट्रोफेनॉल (PNP) को खत्म करने के लिए जाना जाता है, जो डाई और पेस्टिसाइड में पाया जाने वाला एक ज़हरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है। यह आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मरकरी जैसे भारी मेटल को भी झेल सकता है, और 9% तक खारेपन के लेवल पर भी ज़िंदा रह सकता है, जिससे यह प्रदूषित माहौल में बायोरेमेडिएशन के लिए बहुत काम का है। नेताजी महाविद्यालय, बर्दवान यूनिवर्सिटी, IIT (BHU) और हिरोशिमा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे खोजा है, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में है।
- उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए अपने पहले प्राइवेट पॉइंट-इन-स्पेस (PinS) इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर को मंजूरी दी, जो एविएशन नेविगेशन में एक बड़ी तरक्की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (AAI) द्वारा डेवलप और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) द्वारा मंजूर, सैटेलाइट-बेस्ड PinS सिस्टम पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, खासकर खराब मौसम और दूर के इलाकों में सुरक्षित और सटीक हेलीकॉप्टर लैंडिंग को मुमकिन बनाता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के अनुसार, इस पहल से फ्लाइट सेफ्टी, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, आपदा राहत, टूरिज्म, ऑफशोर ऑपरेशन, तीर्थ यात्रा सर्विस, कॉर्पोरेट एविएशन और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

- उडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए अपने पहले निजी पॉइंट-इन-स्पेस (पिनएस) इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया को मंजूरी दी, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने विकसित किया है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंजूरी दी है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स (आईएफआर) के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) तकनीक का उपयोग करते हुए, उपग्रह-आधारित प्रणाली पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) के बिना सटीक लैंडिंग को सक्षम बनाती है। यह बुनियादी ढांचे की लागत को कम करते हुए और आईसीएओ मानकों के साथ संरेखित करते हुए सभी मौसम संचालन, उड़ान सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, आपदा प्रतिक्रिया, अपतटीय मिशन और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाता है।
- स्काईरूट एयरोस्पेस, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बनाए गए ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 को 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन आगमन पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर बना यह चार स्टेज वाला रॉकेट, लो अर्थ ऑर्बिट में 350 kg और सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में 260 kg वजन ले जा सकता है। 3D-प्रिंटेड इंजन, एक ऑल-कार्बन कम्पोजिट स्ट्रक्चर और देसी नेविगेशन सिस्टम वाला यह मिशन, भारतीय स्टार्टअप और इंटरनेशनल कस्टमर्स से पेलोड ले जाते हुए कमर्शियल लॉन्च टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करेगा।
- चिली में NSF-DOE बेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया के सबसे बड़े 3,200-मेगापिक्सल डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करके 10-साल का लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम (LSST) लॉन्च किया। ऑब्जर्वेटरी हर 40 सेकंड में दक्षिणी आसमान को स्कैन करेगी, जिससे हर रात लगभग 10 TB डेटा और कॉस्मिक घटनाओं पर 7 मिलियन तक अलर्ट मिलेंगे। साइंटिस्ट 20 बिलियन गैलेक्सी, डार्क मैटर, सुपरनोवा, ब्लैक होल और ग्रेविटेशनल लेंस की स्टडी करेंगे। IUCAA और NCRA-TIFR के भारतीय रिसर्चर कॉस्मोलॉजी और डायनामिक यूनिवर्स की ग्लोबल समझ को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं।
- रिसर्चर्स ने साइंटिफिक तरीके से कन्फर्म किया है कि बिहार के मुंगेर में 700 साल पुराना बरगद का पेड़, सबसे पुराना और सही तारीख वाला फिक्स बेंचमार्क है। बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज (BSIP) के साइंटिस्ट्स ने अल्फा-सेल्यूलोज सैंपल्स पर एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (AMS) रेडियोकार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया, जिसे IntCal20 कर्व और OxCal सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेट किया गया। क्योंकि बरगद के पेड़ों में सालाना ग्रोथ रिंग्स नहीं होतीं, इसलिए यह इस स्पीशीज़ के लिए पहला वैलिडेट किया गया साइंटिफिक डेटिंग प्रोटोकॉल है। इन नतीजों से लोकल हिस्ट्री में बदलाव हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि यह पेड़ आस-पास की कॉलोनियल स्ट्रक्चर से भी पुराना है और एक पुराने नेचुरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा था।

महत्वपूर्ण दिन समाचार

- इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे हर साल 30 जून को एस्टेरॉयड के असर के खतरों और ग्रहों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2016 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली (UNGA) ने इसे घोषित किया था। यह साइबेरिया में 1908 के तुंगुस्का इवेंट की याद में मनाया जाता है, जो धरती पर दर्ज किया गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड

धमाका था। 2026 की थीम, “ग्रहों की सुरक्षा और एस्टेरॉयड के असर के खतरे,” एस्टेरॉयड का पता लगाने, ट्रैकिंग, रिसर्च और तैयारी में इंटरनेशनल सहयोग पर जोर देती है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वॉर्निंग नेटवर्क (IAWN) और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप (SMPAG) जैसे संगठन खतरनाक नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEOs) पर नज़र रखते हैं और उन्हें कम करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं।

- भारत ने 29 जून 2026 को 20वां स्टैटिस्टिक्स डे मनाया, जो प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के मौके पर मनाया जाता है, जिन्हें मॉडर्न भारतीय स्टैटिस्टिक्स का पिता माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने इसे ऑर्गनाइज़ किया था, 2026 की थीम थी “एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की क्षमता को अनलॉक करना।” इस इवेंट में पॉलिसी बनाने, डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सरकार द्वारा बनाए गए डेटा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। SDGs, लेबर मार्केट और डेटा हार्मोनाइज़ेशन पर खास रिपोर्ट जारी की गई, जबकि स्टैटिस्टिक्स में सुखात्मे नेशनल अवॉर्ड ने स्टैटिस्टिकल साइंस में शानदार योगदान को पहचान दी।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे (CA डे) हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की स्थापना की याद में मनाया जाता है। 2026 का जश्न ICAI का 77वां स्थापना दिवस होगा, जिसके 3.5 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। यह दिन फाइनेंशियल गवर्नेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पहचान देता है। ICAI प्रोफेशनल परीक्षाएं भी आयोजित करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, पॉलिसी बनाने में मदद करता है, और पूरे भारत में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम और अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित करता है।
- नेशनल डॉक्टर डे हर साल 1 जुलाई को भारत में डॉक्टरों को पब्लिक हेल्थकेयर और मेडिकल सर्विस के लिए उनके डेडिकेशन के लिए सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 2026 की थीम, “बिहाइंड द मास्क: हू हील्स द हील्स?”, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के सामने आने वाले स्ट्रेस, बर्नआउट, इमोशनल थकावट और लंबे काम के घंटों जैसी चुनौतियों पर रोशनी डालती है। यह दिन भारत रत्न अवार्डी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन और पुण्यतिथि के तौर पर मनाया जाता है। सेलिब्रेशन में मेडिकल कैंप, अवैरनेस कैंपेन, सेमिनार और डॉक्टरों के कीमती योगदान को पहचानने वाले सम्मान प्रोग्राम शामिल हैं।
- इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 2026, 4 जुलाई 2026 को “शांतिपूर्ण दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स!” थीम के तहत मनाया गया। 1995 से यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त, यह दिन सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक भागीदारी, फाइनेंशियल इनक्लूजन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और सस्टेनेबल खेती में कोऑपरेटिव्स के योगदान को हाईलाइट करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) और COPAC द्वारा गाइडेड, यह आयोजन लोगों पर केंद्रित शासन, शेयर्ड ओनरशिप और कम्युनिटी-ड्रिवन डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, साथ ही इनक्लूसिव और इन्क्लुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के ज़रिए UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को सपोर्ट करता है।

स्थैतिक टेकअवे

पहलू	विवरण
गुजरात	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल, राजधानी: गांधीनगर
महाराष्ट्र	राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस, राजधानी: मुंबई
बिहार	राज्यपाल: आरिफ खान, मुख्यमंत्री: सम्राट चौधरी, राजधानी: पटना
राजस्थान	राज्यपाल: हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री: भजनलाल शर्मा, राजधानी: जयपुर
हरियाणा	राज्यपाल: अशीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री: नायब सैनी, राजधानी: हरियाणा
दिल्ली	राज्यपाल: तरनजीत सिंह, मुख्यमंत्री: रेखा गुप्ता, राजधानी: नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल	राज्यपाल: आरएन रवि, मुख्यमंत्री: सुवेंदु अधिकारी, राजधानी: कोलकाता
ओडिशा	राज्यपाल: हरिबाबू खंभापति, मुख्यमंत्री: मोहन माझी, राजधानी: भुवनेश्वर
सऊदी अरब	देश के प्रमुख: मोहम्मद बिन सलमान
यूएसए	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी: वाशिंगटन डी.सी.
इजराइल	प्रधानमंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू राजधानी: यरुशलम
जापान	प्रधानमंत्री: साने ताकाची, राजधानी: टोक्यो
भारतीय रिजर्व बैंक	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
ओपनएआई	संस्थापक: सैम ऑल्टमैन
आईसीसी अध्यक्ष	जय शाह





LIVE CLASSES

Online **LIVE** Classes for **SSC, Banking, Railways** and Other Govt Exams



**Live & Recorded
Classes**



**PDF Notes &
Study Material**



**Mock Tests &
Practice Questions**



**Doubt Solving
Sessions**

- ✓ **Expert Faculty** with Interactive Classes
- ✓ **Full Exam Syllabus Coverage + Mock Tests**
- ✓ **Courses Available in Hindi, English & Regional Languages**

Get Started Now